ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष- 6-7, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-09, अंक - 316 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए
डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल
22 मई 2026
शुक्रवार

आज का मौसम
42.0 अधिकतम
27.2 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर
दोपहर मेट्रो

Page-7

अपनी मुनाफे की राजनीति के फेर में ट्रम्प ने गवां दी अमेरिका की साख

प्रसंगवश
राजेश सिरोठिया

स्ट्रेट ऑफ़ हॉर्मुज़ को लेकर पश्चिम एशिया में पैदा हुआ तनाव अब केवल सैन्य टकराव का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे छुपे आर्थिक और राजनीतिक हित भी दुनिया के सामने आने लगे हैं। दुनिया के लगभग एक तिहाई तेल व्यापार का रास्ता माने जाने वाला हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य आज वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुका है। ईरान ने इसे बंद करने की चेतावनी देकर अमेरिका पर दबाव बनाने और उसे दुनिया के सामने अस्थिरता का जिम्मेदार साबित करने की कोशिश की। लेकिन इसके जवाब में अमेरिका जिस तरह समुद्री नाकेबंदी को जायज़ ठहराने और उसे स्थायी रूप देने की दिशा में बढ़ रहा है, उसने उसके इरादों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी दुनिया ने अमेरिकी रणनीति का यही चेहरा देखा था। अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों को यूक्रेन की मदद के नाम पर रूस से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप यूरोप की सस्ती रूसी गैस और तेल आपूर्ति बाधित हो गई। इसके बाद अमेरिका ने उन्हीं यूरोपीय देशों को महंगे दामों पर एलएनजी और ऊर्जा संसाधन बेचना शुरू कर दिया। यानी युद्ध और संकट ने अमेरिकी ऊर्जा कारोबार के लिए बड़ा अवसर पैदा कर दिया। अब वही रणनीति भारत के संदर्भ में दिखाई दे रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो की भारत यात्रा से पहले अमेरिका ने भारत को तेल और गैस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका कीमतों और दीर्घकालिक शर्तों पर खुलकर कुछ नहीं कह रहा। उसका स्पष्ट उद्देश्य भारत को रूस से दूर कर अपनी ऊर्जा निर्भरता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव की राजनीति भी है।

भारत के लिए सतर्क रहने का समय

भारत के लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है। ऊर्जा सुरक्षा जरूरी है, लेकिन किसी एक शक्ति पर निर्भरता भविष्य में रणनीतिक संकट पैदा कर सकती है। भारत को संतुलित विदेश नीति और बहुध्रुवीय संबंधों की नीति पर कायम रहना होगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ताकत से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। यदि कोई देश हर संकट को मुनाफे के अवसर में बदलने लगे, तो उसकी साख कमजोर होना तय है। आज अमेरिका उसी चुनौती से जूझता दिखाई दे रहा है।

यहीं से क्वाड जैसे मंचों की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्वाड बनाया था। लेकिन आज जब अमेरिका की प्राथमिकता वैश्विक साझेदारी से अधिक आर्थिक लाभ कमाना दिखाई दे रही है, तब यह चिंता स्वाभाविक है कि कहीं रणनीतिक गठबंधन भी अमेरिकी व्यापारिक हितों का माध्यम तो नहीं बनते जा रहे।

डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीति ने इस धारणा को और मजबूत किया है। ट्रम्प का दृष्टिकोण पारंपरिक कूटनीति से अधिक कारोबारी नजर आता है। दुनिया युद्ध, महंगाई और ऊर्जा संकट से जूझ रही है, जबकि अमेरिका वैश्विक संकटों के बीच अपने आर्थिक हित साधने में लगा दिखाई देता है। ट्रम्प परिवार पर इनसाइडर ट्रेडिंग और कारोबारी लाभ लेने के आरोप भी अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर कर रहे हैं। यूरोपीय देशों का अमेरिका से बढ़ता असंतोष इसका संकेत है। कभी अमेरिका को सबसे भरोसेमंद साझेदार मानने वाले देश अब उससे दूरी बनाने लगे हैं। दूसरी ओर चीन ताइवान को लेकर लगातार आक्रामक है और अमेरिका की प्रतिक्रिया पहले जैसी निर्णायक नहीं दिखती। इससे उसकी वैश्विक साख पर भी असर पड़ा है।

INDIAN PREMIER LEAGUE
हैदराबाद-बैंगलुरु, समय : शाम 7.30 बजे

न्यूज विंडो

राज्यसभा की 26 सीटों के लिए 18 जून को मतदान

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन मतगणना भी होगी। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 9 जून को नामांकन की जांच की जाएगी, 11 जून को नामांकन वापस लिया जाएगा। इसके बाद 12 राज्यों की 2 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। चुनाव 10 राज्यों में होंगे, जहां मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग-अलग तारीखों पर रिटायर हो रहे हैं।

नीट पेपर लीक में पुणे से लातूर तक सीबीआई की पूछताछ

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजुकेशनल कंसल्टेंसी संचालक शुभम खैरनार, निलंबित जूनियर कॉलेज शिक्षिका मनीषा मंधारे, ब्यूटी पार्लर मालकिन मनीषा वाघमारे और लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ इस मामले के केंद्र में आ गए हैं।सीबीआई अब मामले से जुड़े पैसों के मनी ट्रेल, डिजिटल फुटप्रिंट्स और संदिग्ध लाभार्थियों की बढ़ती सूची की पड़ताल कर रही है। पूछताछ के लिए खैरनार को पुणे लाया गया है। 3 मई को हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक करने और उसे आगे फैलाने में कथित भूमिका को लेकर मंधारे और वाघमारे से भी फिर से पूछताछ की गई।

गुरदासपुर में टूरिस्ट बस पलटी दो छात्रों की मौत, 8 यात्री घायल

बटाला। अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर कलेर खुर्द के पास अमृतसर से जम्मू जा रही एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि पांच यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान बस के पीछे से आ रही पांच गाड़ियां भी आपस में टकरा कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। बस में यात्रयों के अनुसार जब बस पलटी उस समय सभी सोए हुए थे। जब आंख खुली तो पता चला कि बस पलटने से पीछे वाला शीशा टूटने के कारण कुछ यात्री बस से बाहर गिर गए हैं। एक यात्री युवक के अनुसार उसके दो दोस्तों की बस पलटने से मौके पर ही मौत हो गई।

आज का कार्टून

खतरे की घंटी...सामान्य से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है प्रशांत महासागर का पानी

झुलसाने वाली गर्मी के बीच 'अल - नीनो' का खतरा, टूटेंगे तपिश के सभी रिकॉर्ड !

नई दिल्ली, एजेंसी

इस साल अन नीनो के प्रकोप का खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके पहले ही पूरे देश के मैदानी इलाकों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। मई-जून में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन इंतजार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में गर्मी से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। उत्तर प्रदेश का बांदा तो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। यहां का तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस से उपर बना हुआ है और यह बीते कई दिनों से गर्मी के मामले में दुनिया के टॉप 3 शहरों में शामिल हो रहा है। वहीं, अब दिल्ली पर भी खतरा मंडरा रहा है। अल नीनो के बिना ही तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। अगर अल नीनो ने दस्तक दी तो स्थिति बिगड़ सकती है और दिल्ली का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है।

अमेरिकी मौसम एजेंसी एनओएए के अनुसार, मई और जून के बीच अल नीनो के विकसित होने की 82 से 98 फ़ीसदी तक संभावना है। यह स्थिति मजबूत होते हुए 'सुपर अल नीनो' का रूप भी ले सकती है। इसके प्रभाव से मॉनसून कमजोर हो सकता है, जिससे सामान्य से कम बारिश और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके प्रभाव से दुनियाभर में भीषण गर्मी पड़ने और तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि होने की आशंका है।

इस बार खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। मध्य प्रशांत में तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और नीचे की सतह पर गर्म पानी का बड़ा भंडार जमा हो गया है.। अगर यही तापमान 2 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है, तो यह 'सुपर एल नीनो' कहलाएगा। पिछले 70 सालों में ऐसा केवल 1982, 1997 और 2015 में हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार यह 150 साल का सबसे ताकतवर एल नीनो बन सकता है।

इस बार मानसून का अनुमान

केरल	26 मई
मध्यप्रदेश	15 से 20 जून
उत्तर प्रदेश	15 से 22 जून
दिल्ली-एनसीआर	25 जून तक
राजस्थान	25 जून से 5 जुलाई

स्पेनिश भाषा से आया शब्द

अल नीनो को स्पेनिश भाषा के शब्द 'एल नीन्यो' से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 'छोटा बच्चा' या 'बालक'। कहा जाता है कि क्रिसमस के आसपास समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता था, तो मछुआरों ने इसे मसीह के शिशु रूप से जोड़कर 'एल नीनो ' नाम दे दिया। अल नीनो से पूर्व से पश्चिम चलने वाली हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या रुक जाती हैं। इससे गर्म पानी जो पश्चिम (एशिया के पास) में जमा होता है, वह वापस पूर्व की ओर यानी दक्षिण अमेरिका की तरफ बहने लगता है। इससे पूरे प्रशांत महासागर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

ऐतिहासिक भोजशाला में सुबह हुई महाआरती

धार, दोपहर मेट्रो

धार की ऐतिहासिक भोजशाला में लंबे अंतराल के बाद आज शुक्रवार को हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा-अर्चना का अधिकार मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंचे और मां वाग्देवी की पूजा-अर्चना की।

भोजशाला मामले में याचिका दायर करने वाले कुलदीप तिवारी भी पहुंचे, जिनका श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। कुलदीप तिवारी ने परिसर से मेहराब और अयातुल्ला कुर्सी हटाने की मांग की है। इधर, मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर आज भोजशाला मामले में सुनवाई की संभावना लगभग खत्म हो गई है। याचिकाकर्ता के वकील मनीष गुप्ता ने मेंशन नही लेने की पुष्टि की।

सुबह 9 बजे भोजशाला में महाआरती हुई, जबकि दोपहर 12 बजे से परिसर में बड़ा आयोजन किया गया। आंदोलन में बलिदान देने वाले तीन शहीद परिवारों के सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। इधर, पूरे धार शहर में हाई अलर्ट घोषित कर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। वहीं मस्जिद पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

दोबारा पोस्टमॉर्टम के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर

ट्विशा शर्मा की मौत की सीबीआई जांच होगी, सरकार ने की सिफारिश

भोपाल, दोपहर मेट्रो। चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में मामले की जांच हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई है।

सरकार ने सीबीआई को इस मामले से जुड़े अपराध, साक्ष्य, दुष्प्रेरण और अन्य पहलुओं की जांच की अनुमति भी दे दी है। माना जा रहा है कि सीबीआई अब पूरे मामले की नए सिरे से जांच करेगी। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई है। उधर, ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करने की मांग भोपाल कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद आज उनके परिवार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। उनका कहना है कि एम्स भोपाल में हुआ में हुआ पोस्टमॉर्टम पूर्व जज गिरिबाला सिंह के परिचित डॉक्टरों द्वारा किया गया था, इसलिए उस पर भरोसा नहीं है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि जिस स्थिति में त्विशा का शव है , उसमे दोबारा पोस्टमॉर्टम हो पाएगा या नहीं। हाईकोर्ट में लगी याचिका में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग भी की गई है। आज ही ट्विशा के पति समर्थ सिंह की जमानत याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है।

कैराना सांसद इकरा हसन पर एफआईआर दर्ज

सहारनपुर। यूपी में शामली के गांव जसाला में कश्यप समाज के युवक मोनू की मौत के मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। इस मामले में कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि सांसद और उनके समर्थकों ने सड़क जाम कर यातायात व्यवस्था प्रभावित की थी। इस मामले में 7 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 20 से 25 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। नामजद आरोपियों में सांसद इकरा हसन के अलावा पूर्व राज्यमंत्री मांगेराम कश्यप, तेजपाल सिंह, अजय, अनुज, शीशपाल और सत्यपाल के नाम शामिल हैं।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस प्री-समिट

भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के ऑडिटोरियम में आज इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) प्री-समिट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन वन्यजीव संरक्षण और त्वरित रेस्क्यू कार्यों में उपयोग किए जाएंगे।

मेट्रो एंकर | आईआईटी दिल्ली की स्टडी, होम डिलीवरी करने वालों को आउटडोर कैटेगरी में रखने की सिफारिश

45 डिग्री में 14 घंटे काम... महीने की 2 छुट्टी, कमाई सिर्फ 25 हजार

नई दिल्ली, एजेंसी

आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी में सामने आया है कि गिग वर्कर्स रोजाना 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। गर्मी की चिलचिलाती धूप में भी फास्ट डिलीवरी का प्रेशर उन पर है। ऐसे में आईआईटी की रिसर्च टीम ने सिफारिश की है कि गिग वर्कर्स को आउटडोर वर्कर्स की कैटेगिरी में रखा जाए और उनके लिए भी काम के घंटे, हीट प्रोटेक्शन के नियम बनें।

स्टडी का कहना है कि 56 फ़ीसदी गिग वर्कर्स रोज 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, यानी दिन का बड़ा हिस्सा तपती गर्मी में सड़क पर बीत रहा है। भीषण गर्मी के दौरान सिर दर्द, थकान, मसल्स क्रैम्प, हीट रैश जैसी शिकायतें आम हैं। रिसर्च कहती हैं कि लंबे समय तक ऐसे ही काम करना उनके स्वास्थ्य पर और बुरा असर डाल सकता है। आईआईटी के 'ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजुरी प्रिवेंशन सेंटर ' की रिसर्च टीम की स्टडी ने गिग इकॉनमी के चमकदार मॉडल के पीछे छिपी गंभीर तस्वीर को सामने रखा है।

वैसे तो देश के ज्यादातर शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है लेकिन स्टडी में दिल्ली के 45 डिग्री तापमान का जिक्र किया गया है और लू चल रही है। ईस्ट ऑफ कैलाश से स्कूटी में 10-10 मिनट में डिलीवरी कर रहे संतोष कुमार कहते हैं, फास्ट डिलीवरी का प्रेशर तो है ही मगर इस वक्त गर्मी सबसे बड़ी मुश्किल है। कल तेज धूप में 14 घंटे डिलीवरी की। दिन में घंटेभर का ब्रेक रखता हूं, महीने की दो छुट्टी लेता हूँ तो 25-28 हजार रुपये कमा लेता हूं। गिग वर्कर्स की इन्हीं मुश्किलों पर आईआईटी दिल्ली की इस स्टडी ने सवाल किया है।

स्टडी को लीड कर रहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर दीप्ति जैन कहती हैं, गिग वर्क का मतलब ही है काम के हिसाब से कमाई। ये बहुत नई इकनॉमी है, ये ना तो आउटडोर वर्कर्स हैं, ना फॉर्मल एम्प्लॉई। आज तक हीट एक्शन प्लान में गिग वर्कर्स को आउटडोर वर्कर्स की तरह नहीं देखा गया है, जबकि सुरक्षा प्रावधान होने चाहिए।

किस कीमत पर गिग इकनॉमी?

स्टडी का बड़ा सवाल है कि क्या भारत की तेजी से बढ़ती गिग इकॉनमी वर्कर्स की सेहत और सुरक्षा की कीमत पर खड़ी हो रही है? राइडर्स बताते हैं कि वो असुरक्षित स्थितियों में 12 से 18 घंटे काम करके 20 से 60 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं। हाल ही में गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने भी दिल्ली सरकार से मांग की है कि 40-45 डिग्री तापमान और उमस के कारण उनका काम बड़ी चुनौती बना हुआ है। डिलीवरी राइडर्स और बाकी ऐप बेस्ड कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच ब्रेक मिले, शेड वाले रेस्ट स्पॉट बनें, पीने का पानी और इमरजेंसी हेल्थ केयर की सुविधा मिले।

काटजू अस्पताल में महिला ने एक साथ तीन बेटों को दिया जन्म

विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एलएससीएस आपरेशन से कराई सुरक्षित डिलीवरी

» मां और तीनों नवजात पूरी तरह स्वस्थ, परिवार में खुशी का माहौल

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित डॉ. कैलाशनाथ काटजू मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान (काटजू अस्पताल) में गुरुवार को एक महिला ने एक साथ तीन स्वस्थ बेटों को जन्म दिया। अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने सफलतापूर्वक ट्रिपलेट्स (तीन बच्चों) की डिलीवरी कराई।

कठिन था ऑपरेशन

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार महिला की डिलीवरी एलएससीएस (लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन) ऑपपरेशन के माध्यम से की गई। यह जटिल प्रक्रिया विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में संपन्न हुई। मां और तीनों नवजात पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

टीम वर्क से मिली सफलता

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सफल ऑपरेशन के बाद परिजनों और अस्पताल स्टाफ में खुशी का माहौल है। चिकित्सकों ने इसे बेहतर टीमवर्क और समय पर उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं का परिणाम बताया।ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. राकेश जैन और डॉ. ऋतुराज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं नवजात शिशुओं की देखभाल शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. आरती जैन और डॉ. सौरभ जैन ने की। पूरी प्रसूति प्रक्रिया स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. ज्योति खरे की देखरेख में संपन्न हुई।

गेहूं खरीदी तारीख बढ़ने से मंडियों में आई रौनक

भोपाल। दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश के किसानों में गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ने के बाद से ही उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में मंडी आ रही किसानों की उपज खरीदी का टारगेट भी बढ़ गया है। इससे किसान बेहद खुश है। बड़ी संख्या में किसान गेहूं ही नहीं, सोयाबीन, चना, सरसों, मक्का, जौ समेत औषधीय उपज भी लेकर मंडी में बेचने को पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं 21 मई 2026 गुरुवार शाम को मंडी में ताजा भाव क्या रहें।

राजस्थान बार्डर से लगी नीमच मंडी में बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। यह मंडी अनाज, दाल, दलहन के अलावा औषधीय उपज के लिए भी प्रसिद्ध है। क्योंकि यहां बड़ी संख्या में अश्वगंथा, खसखस, कलौंजी, अजवाइन आदि उपज भी खरीदी जाती है। नीमच मंडी में लहसुन, पोस्ता और अश्वगंधा में तेजी रही, जबकि प्याज और मक्का कमजोर रहा।

नीमच मंडी में न्यूनतम और अधिकतम भाव जारी हो गए हैं। गेहूं के भाव 2,530 से 2,955 तक रहे। सोयाबीन अधिकतम 7,221 के भाव में खरीदा गया। लहसुन के भाव में तेजी रही। यह 1,130 से 19,400 तक के भाव में बिका। एवरेज भाव 10300 रुपए प्रति क्विंटल रहे। अश्वगंधा की बात करें तो अधिकतम भाव 19651 के भाव पर खरीदी गई। खसखस 71000 से 1 लाख 60 हजार के भाव पर खरीदी गई।

ज्यादा ट्रेनों से व्यापार को मिलेगा बड़ा फायदा

बेहतर कनेक्टिविटी: संत हिरदाराम नगर बना भोपाल का दूसरा जंक्शन

भोपाल।दोपहर मेट्रो

संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन को अब भोपाल का दूसरा रेलवे जंक्शन घोषित कर दिया गया है। रेलवे के आदेश जारी होने के बाद यह स्टेशन अब सिर्फ एक सामान्य रेलवे स्टेशन नहीं रहेगा, बल्कि जंक्शन के रूप में नई पहचान बनाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं मिलने के साथ क्षेत्र के व्यापार, परिवहन और रोजगार को भी नई गति मिलेगी।

अब बढ़ेगी ट्रेनों की कनेक्टिविटी

अब तक संत हिरदाराम नगर एक सामान्य स्टेशन के रूप में काम कर रहा था, जहां सीमित रेल संचालन होता था। जंक्शन बनने के बाद यहां से विभिन्न दिशाओं में रेल संपर्क का विस्तार किया जा सकेगा। इससे भविष्य में नई ट्रेनों के संचालन और ट्रेनों के ठहराव बढ़ने की संभावना भी मजबूत हुई है। यात्रियों को भोपाल स्टेशन पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी और उन्हें वैकल्पिक रेल सुविधा मिल सकेगी।

व्यापार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

रेलवे जंक्शन बनने का सबसे बड़ा फायदा व्यापारिक गतिविधियों को होगा। माल परिवहन मजबूत होने से स्थानीय व्यापारियों और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों

में होटल, परिवहन और छोटे व्यवसायों के बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी क्षेत्र में रेलवे जंक्शन बनने से आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ती हैं।

क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई दिशा

विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे हुजूर विधानसभा और संत नगर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार जताया।

अमृत स्टेशन योजना से बदल रही तस्वीर

संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर अमृत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। नई सुविधाओं और जंक्शन के दर्जे के बाद आने वाले समय में यह स्टेशन भोपाल के प्रमुख रेलवे केंद्रों में शामिल हो सकता है।

भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त एक माह में लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश

भोपाल। दोपहर मेट्रो

भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन अब बड़े स्तर पर अभियान चलाने जा रहा है। कलेक्टोरेट में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने साफ निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियों से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और लंबित राजस्व प्रकरणों का तय समय सीमा में निराकरण हो। बैठक में कलेक्टर ने भूमि आवंटन, धारणाधिकार, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि तीन माह से अधिक पुराने सीमांकन प्रकरणों का अगले एक महीने में अनिवार्य रूप से समाधान किया जाए। राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।

मानसून से पहले अतिक्रमण और सुरक्षा जांच पर जोर

आगामी मानसून को देखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण, फायर सेफ्टी, पटाखा दुकानों और गोदामों के निरीक्षण तेज करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों की अनुभाग स्तर पर बैठकें आयोजित कर तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में एडीएम सुमित कुमार पांडे, प्रकाश नायक, अंकुर मेश्राम, पीसी शाक्य सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

नगर निगम और एसडीएम कार्यालयों के बीच समन्वय बढ़ाने पर दिया जोर

कलेक्टर ने कॉलोनी सेल, नगर निगम और एसडीएम कार्यालयों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि वैध और अवैध कॉलोनियों से संबंधित शिकायतों की तथ्यात्मक जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही भू-राजस्व, खनिज राजस्व और अन्य शासकीय बकाया की शत-प्रतिशत वसूली पर जोर दिया। बैठक में नक्शा शुद्धिकरण, खसरा-खतौनी में त्रुटि सुधार और भूमि अभिलेखों को अपडेट करने के काम को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए, ताकि जमीन विवादों में कमी लाई जा सके। सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस पोर्टल, जनसुनवाई और अन्य शिकायत प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नागरिकों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण प्रशासन की प्राथमिकता रहे। सभी एडीएम और एसडीएम को तहसीलदार न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करने तथा पारित आदेशों के पालन की निगरानी के निर्देश दिए गए। एक माह के भीतर लंबित आदेशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले

हाउसिंग बोर्ड के मकान लोकतंत्र सेनानियों के लिए होंगे आरक्षित

भोपाल। दोपहर मेट्रो

एमपी हाउसिंग बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक गुरुवार को पर्यावास भवन में आयोजित हुई। बैठक में मकान आवंटन, आरक्षण व्यवस्था और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

हाउसिंग बोर्ड के मकानों में अब लोकतंत्र सेनानियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अभी तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब इस श्रेणी में आपातकाल के दौरान मीसा के तहत जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को भी शामिल किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान मीसा के तहत जेल गए लोगों को लोकतंत्र सेनानी माना जाता है।बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है।बैठक से पहले नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नवनियुक्त बोर्ड अध्यक्ष को मंडल के कार्यों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी। बैठक में एसीएस संजय दुबे, बोर्ड कमिश्नर गौतम सिंह सहित टीएनसीपी, हूडको और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उपस्थित रहे। हाउसिंग बोर्ड ने आरक्षित वर्ग के तहत मकान लेने वालों के लिए समग्र आईडी अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति आरक्षण का लाभ दोबारा न ले सके। नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी में एक व्यक्ति केवल एक बार ही मकान प्राप्त कर सकता है।

आएंगे नए प्रोजेक्ट

बैठक में नए प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड पूलिंग योजना पर शीघ्र काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। इससे बोर्ड को जमीन खरीदने में बड़ी पूंजी लगाने से राहत मिलेगी और किसानों को भी फायदा होगा। बोर्ड कमिश्नर गौतम सिंह ने भोपाल में प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा और नए कलेक्टर कार्यालय प्रोजेक्ट की जानकारी संचालक मंडल को दी। पुराने कलेक्टर कार्यालय की जगह 217 करोड़ रुपये की लागत से नया प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा, जिसमें कलेक्टोरेट, कमिश्नर और आईजी कार्यालय एक ही परिसर में होंगे।

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम तेज, 50 साल बाद शिफ्ट होंगी आरा मशीनें

भोपाल। दोपहर मेट्रो

शहर के बीच से आरा मशीन टिंबर मार्केट की शिफ्टिंग पर 50 साल बाद बात बन गई। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की जद में आ रही पुल पातरा से ग्रांड होटल के पीछे तक 36 आरा मशीनों को हटाने पर सहमति बन गई है। आरा मशीन संचालकों को एयरपोर्ट के पास रातीबड़ में जगह आवंटित कर दी गई। 26 आरा मशीनों के दस्तावेज अपडेट है, जबकि दस आरा मशीनों के दस्तावेजों का अपडेटेशन बाकी है। जो अपडेट है, उन्हें नई जगह पर काम शुरू करने की अनुमति पहले दिन से ही मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की एनओसी बाकी है, जिसके बाद नई जगह पर काम शुरू हो जाएगा। रातीबड़ में लघु उद्योग निगम ने यहां आरा मशीनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। 12 एकड़ में 36 आरा मशीनों के लिए पूरी तरह नया क्षेत्र विकसित कर दिया गया है। अफसरों का कहना है कि शिफ्टिंग के लिए पांच करोड़ रुपए भी दिए गए। शहर में कुल 165 आरा मशीनें है। टिंबर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष बदर आलम का कहना है कि आरा मशीनों की शिफ्टिंग पर सहमति बन गई है। उद्योग नियमों के अनुसार प्लॉट आवंटन हो चुका है। अब आरा मशीन संचालक अपने स्तर पर शिफ्टिंग शुरू कर देंगे। एक माह में पुल पातरा से ग्रांड होटल के पीछे तक की आरा मशीनें हट जाएगी। सिटी एसडीएम दीपक पांडेय ने बताया कि रातीबड़ में आरा मशीनों के लिए जगह तय कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो गया। स्ट्रीट लाइट और कुछ काम बाकी है, इस सप्ताह ये काम पूरा हो जाएगा। डीएफओ की एनओसी मिलना है, नई जगह पर काम शुरू किया जा सकेगा।

मेट्रो लाइन, अंडरग्राउंड रैंप का काम हो सकेगा शुरू

मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा टिंबर मार्केट है। पुल बोगदा से पुल पातरा के बीच एलिवेटेड और इसके बाद अंडरग्राउंड लाइन का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है। टिंबर मार्केट के दुकानदारों की सबसे बड़ी ताकत उनका कारोबार है। शहर की जरूरत की 60 फीसदी लकड़ी का सामान और लकड़ियां यहीं से जाती है। सभी दुकानें हटने से फर्नीचर व इसके लिए जरूरी लकड़ियों की आपूर्ति प्रभावित न हो इसका भी ध्यान रखना होगा। इसी कमजोर नब्ज पर लंबे समय से रोड किनारे कारोबार चल रहा है।

सुनसान गली में टिंबर की दुकानें

पुल बोगदा से पुल पातरा के बीच करीब दो किमी लंबी रोड पहले दुकानदारों और ग्राहकों से भरी रहती थी, लेकिन मेट्रो के काम के चलते हुई तोड़फोड़ ने पूरी रोड पर लगभग सन्नाटे की स्थिति बना दी। यहां सिर्फ लकड़ी बाजार ही बचा है और जब तक ये नहीं हटता काम मुश्किल है। ऐशबाग के 90 डिग्री ब्रिज के बाद इन्हीं टिंबर की दुकानों के बीच अंडरग्राउंड लाइन का काम शुरू होगा।

मेट्रो एंकर

रोजाना 175 टैंकरों की जरूरत, शहर पहुंच रहे सिर्फ 155 से 160 टैंकर

संकट गहराया: कई पेट्रोल पंप ड्राय, सप्लाई थमने से परेशान हो रहे उपभोक्ता

भोपाल। दोपहर मेट्रो

एमपी में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई चेन प्रभावित होने से ईंधन का संकट गहराने लगा है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कई पेट्रोल पंप 'ड्राई' (ईंधन खत्म) होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। पंप संचालकों का आरोप है कि तेल कंपनियां अब ईंधन के लिए पहले ही एडवांस भुगतान करवा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद समय पर पेट्रोल-डीजल की डिलीवरी नहीं की जा रही है। टैंकरों के देरी से पहुंचने के कारण पंपों पर ईंधन खत्म हो जाता है और नया स्टॉक आने तक उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ता है। पेट्रोल के लिए गुरुवार को वाहन चालक परेशान होते रहे। आमजन ने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की।

शहर के पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन में खड़े ग्राहकों ने बताया कि दाम में इजाफा होने की आशंका से कंपनियां अपना स्टॉक जानबूझकर कम सप्लाई कर रही हैं। जनता पर महंगाई की मार के साथ आम दिनों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाने की मजबूरी भी थोपी जा रही है। महेश कुमार ने बताया कि पंपों पर चक्कर काटने के बाद तीसरे

पंप पर आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा। पेट्रोल न मिलने से काम पर जाने में देरी हो गई। किसान सतीश यादव के अनुसार ट्रैक्टर के लिए डीजल लेने आया था, लेकिन पंप बंद मिला। कंपनियों को समय पर तेल देना चाहिए, खेती का सीजन प्रभावित हो रहा है। यदि कोई पेट्रोल पंप पर 5000 रुपए से अधिक का पेट्रोल या दस हजार रुपए से अधिक का डीजल खरीदता है तो उसे वैध कारण बताना होगा। यदि उसका उद्देश्य औद्योगिक- व्यवसायिक है तो फिर उसे पेट्रोलियम पंप से नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों से पेट्रोलियम की स्थिति पर बैठक में ये तय किया गया। गौरतलब है कि औद्योगिक उद्देश्य वाले डीजल की कीमत में 50 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। यहां बैठक में पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि पंप पर सस्ते पेट्रोल की वजह से औद्योगिक उपयोग वाले बल्क में डीजल लेने पहुंच रहें। इससे आमजन को पेट्रोल- डीजल में कमी हो सकती है। इसपर खाद्य अफसरों ने बल्क में खरीदी करने वालों से कारण पूछने के निर्देश दिए। मप्र पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह बताते हैं कि जितनी डिमांड हो रही है, उस हिसाब से डीजल-पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही है। रेट बढने् के बाद भी कंपनियों को घाटा होने से सप्लाई प्रभावित है। समय पर टैंकर न मिलने से 20 फीसदी पंप रोजाना ड्राई हो रहे हैं। इधर एचपीसीएल के रीजनल मैनेजर कपिल राय के अनुसार डीजल-पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, सामान्य रूप से सप्लाई जारी है। पंप बंद होने के पीछे डीलर्स के दूसरे कारण हो सकते हैं। यह बात हमने डीलरों को भी बता दी है।

कंपनियों का दावा: ईंधन की कोई किल्लत नहीं

तेल कंपनियों के अधिकारियों ने ईंधन की कमी के दावों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कोई किल्लत नहीं है और पहले के मुकाबले सप्लाई को और बढ़ाया गया है। गुरुवार को इंडियन ऑयल के जेल पहाड़ी स्थित कार्यालय में एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल के अधिकारियों की पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ एक बैठक भी हुई। इसमें कंपनियों ने साफ किया कि सप्लाई चेन में कोई समस्या नहीं है और पंप बंद होने के अन्य व्यावसायिक कारण हो सकते हैं। बढ़ोतरी के बाद भी घाटा : अकेले भोपाल जिले में जहां रोजाना 175 टैंकर डीजल-पेट्रोल की जरूरत होती है, वहीं वर्तमान में केवल 155 से 160 टैंकर ही पहुंच पा रहे हैं। इस समय देश में उद्योग पूरी क्षमता से चल रहे हैं और कृषि कार्य भी जारी है, जिससे कमर्शियल व सामान्य डीजल की मांग काफी बढ़ गई है।

गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार

भोपाल। दोपहर मेट्रो

क्राइम ब्रांच ने पंजाब मेल ट्रेन से गांजा तस्करी कर भोपाल पहुंचे 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 4 लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपी घरेलू सामान की आड़ में गांजा तस्करी कर भोपाल में सप्लाई की तैयारी कर रहे थे। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपी घरेलू सामान टोकरी, टप और तगाड़ी की आड़ में गांजा तस्करी कर रहे थे। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए सामान को इस तरह पैक किया था, ताकि किसी को शक न हो। पंजाब मेल ट्रेन के जरिए यह खेप भोपाल लाई गई थी। आरोपियों की गतिविधियों पर पहले से नजर रखी जा रही थी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी करारिया जंगल के रास्ते छोला क्षेत्र में गांजा सप्लाई करने की तैयारी में थे।

पांढुर्णा जिले के ग्राम आमला में मध्यप्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और लोक परंपराओं की अनुपम छटा उस समय देखने को मिली, जब जनजातीय लोक कलाकारों ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल के समक्ष रंगारंग लोक नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियाँ दीं। पारंपरिक वेशभूषा, मधुर लोकधुनों और उत्साह से भरपूर नृत्य शैली ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उल्लास से सराबोर कर दिया। कलाकारों की प्रस्तुति में जनजातीय जीवन की सादगी, प्रकृति के प्रति प्रेम, सामाजिक एकता और पारंपरिक मूल्यों की अद्भुत झलक दिखाई दी।

उज्जयिनी की सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा नया आधार

शिप्रा की आध्यात्मिक धारा का नया दस्तावेज हुआ तैयार

उज्जैन, दोपहर मेट्रो

देश की पवित्रतम नदियों में शुमार मोक्षदायिनी 'शिप्रा नदी' की आध्यात्मिक धारा का नया दस्तावेज (ग्रंथ) तैयार हुआ है। ये दस्तावेज 'कालिदास संस्कृत अकादमी' ने स्कन्द पुराण के संदर्भों, हिन्दी अनुवाद और दुर्लभ सामग्री के साथ 'श्री शिप्रा महिमा' और 'शिप्रास्तोत्रम्' नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किए हैं, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को शिप्रा की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पुराणिक महिमा से परिचित कराना है। अकादमी के निदेशक डॉ. गोविन्द गंधे सहित शिक्षाविद् इसे उज्जयिनी की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपरा के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखे रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से शिप्रा नदी के महत्व पर प्रामाणिक और सरल भाषा में उपलब्ध साहित्य की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इन दोनों पुस्तकों के प्रकाशन से अब शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों, धर्माचार्यों और आम श्रद्धालुओं को एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

शिप्रा भारतीय सांस्कृतिक की चेतना

डॉ. गन्धे ने बताया कि स्कन्द पुराण के अवन्ती क्षेत्र महात्म्य में उज्जयिनी, यहां के देवालयों, जलतीर्थों और विशेष रूप से शिप्रा नदी का अत्यंत विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। शिप्रा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना, मोक्ष परंपरा और धार्मिक आस्था की जीवंत धारा है। इसके बावजूद आमजन तक शास्त्रीय जानकारी सहज रूप में उपलब्ध नहीं थी। धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और शिप्रा संरक्षण को लेकर चल रही राष्ट्रीय चर्चा के बीच इन ग्रन्थों का प्रकाशन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रयास शिप्रा नदी को केवल आस्था नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के वैश्विक प्रतीक के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा।

प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के प्रयास हो रहे फलीभूत : मुख्यमंत्री बोले-

दुग्ध उत्पादकों को गत वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक हुआ भुगतान, रोजाना हो रहा 9.67 लाख किलो का संकलन

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के प्रयास फलीभूत होने लगे हैं। समन्वित प्रयासों से मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन बढ़ाते हुए लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। प्रदेश में प्रतिदिन 9.67 लाख किलोग्राम औसत दुग्ध संकलन की उपलब्धि दर्ज हुई है। यह गत वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है। इस उपलब्धि को निरंतर बढ़ाना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में पशुपालन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि गत छह माह में 11 लाख किलोग्राम से अधिक औसत प्रतिदिन दुग्ध संकलन हुआ है। दुग्ध संघों ने दुग्ध उत्पादक किसानों को गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान किया है। पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनू योजना, आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, मवेशियों के स्वास्थ्य की बेहतर देखरेख,चारा उत्पादन और उपलब्धता,पशु पोषण,स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना, क्षीरधारा ग्राम योजना,ब्रीडर एसोसिएशन,दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, गोरस ऐप, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के कार्यों और एनडीडीबी द्वारा दिए जा रहे सहयोग की विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की।

दुग्ध उत्पादन में नम्बर वन बनाना है प्रदेश को

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे क्रम पर है। हमारा लक्ष्य प्रथम क्रम पर आने का है। इस दिशा में प्रारंभ किए गए प्रयास सफल हो रहे हैं। प्रदेश में 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। ग्वालियर डेयरी प्लांट के आधुनिकीकरण, शिवपुरी डेयरी प्लांट को पुनर्जीवन देने, इंदौर में 3 लाख लीटर रोजाना क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट की शुरूआत जैसे ठोस कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निश्चित ही इन प्रयासों से प्रदेश को दुग्ध उत्पादन और विक्रय के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहयोग मिला है। ये प्रयास जारी रहना चाहिए।

बीते वर्ष दुग्ध उत्पादकों को किया 1609 करोड़ रूपये का भुगतान

प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मार्गदर्शन में हुए कार्यों से वर्ष 2024-25 में 1398 करोड़ की तुलना में वर्ष 2025-26 में दुग्ध उत्पादकों को 1609 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान (गत वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक) में सफलता मिली है। दुग्ध उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रणाली से विभिन्न दुग्ध संघों में खरीद मूल्य में 2.50 से 8.50 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। किसानों की आय बढ़ने से उनके जीवन में समृद्धि आ रही है।

सांची ब्रांड को सुदृढ़ करने में मिली कामयाबी

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में विपणन और ब्रांड सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत सांची ब्रांड को लोकप्रिय बनाते हुए विभिन्न उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में भी सफलता मिली है। मूल्यसंवर्धित उत्पादों में घी की बिक्री 17प्रतिशत बढ़ी है। पनीर, दही, छाछ और फ्लेवर्ड दूध की बिक्री में भी वृद्धि दर्ज हुई है। बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के प्रयास भी किए गए। बैठक में प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव और अन्य वरिष्ठ

मप्र में पेट्रोल-डीजल लेने पर अब देना होगा हिसाब!

5 हजार से ज्यादा के पेट्रोल और 10 हजार के डीजल पर बताना होगा कारण

भोपाल, दोपहर मेट्रो

जिले में तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों को तय सीमा से अधिक पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पंप उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसी समस्या के बीच कुछ पंपों पर स्टॉक की कमी तक हो रही है। ऐसे में समस्या का समाधान करने के लिए कलेक्ट्रेट में गुरुवार को तेल कंपनी, पेट्रोल पंप संचालक व खाद्य विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जिसमें पंप संचालकों के एसोसिएशन ने बताया कि उनको समय पर और पर्याप्त पेट्रोल-डीजल नहीं मिल रहा है, जबकि तेल कंपनियों का दावा है कि नियमित रूप से पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

साथ ही संचालकों ने कहा कि यदि वह ग्राहकों की मांग के अनुसार पेट्रोल-डीजल आपूर्ति कर देते हैं तो कंपनियां उन्हें नोटिस थमा देती हैं, जबकि कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पांच हजार से अधिक का पेट्रोल व 10 हजार रुपये से अधिक का डीजल देने पर कारण बताना होगा। जानकारी के अनुसार जिले में इंडियन ऑयल, भारत, एचपी सहित अन्य कंपनियों के मिलाकर कुल 192 पेट्रोल पंप स्थित हैं, जिन पर प्रतिदिन 12 लाख लीटर डीजल, नौ लाख लीटर पेट्रोल की खपत होती है। ऐसे में बुधवार को कटारे पेट्रोल पंप और रायसेन रोड स्थित प्रभात पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों, संचालकों और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में बैठक रखी।

कंपनियों की दलील- 20 प्रतिशत बढ़ी खपत

जिसमें कंपनियों ने बताया कि पेट्रोल व डीजल की किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, बल्कि पहले की अपेक्षा 20 प्रतिशत खपत अधिक हो रही है। दोनों पंपों के द्वारा विस्फोटक लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं करवाया था, जिस वजह से उन्हें आपूर्ति नहीं की गई है। जबकि अन्य सभी पंपों पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा बताया गया कि 180 टैंकरों से पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति की जा रही है, किसी तरह की कोई किल्लत या परेशानी नहीं है। इस पर मध्यप्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बताया कि जब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो पंपों पर मांग के अनुरूप पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं दिया जा रहा है? हर दिन कोई न कोई पंप पर स्टॉक खत्म क्यों हो रहा है?

गेहूं उपार्जन में साइबर ठगी से हड़कंप, नाथ ने सरकार को घेरा

किसान सम्मान निधि से लाखों नाम कटने और भुगतान की गड़बड़ी पर उठाए सवाल

भोपाल , दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। किसानों के खातों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान नहीं पहुंचने और राशि संदिग्ध खातों में ट्रांसफर होने के मामलों ने प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। कमलनाथ ने जारी बयान में कहा कि शिवपुरी जिले में सरकारी गेहूं खरीद के बाद किसानों को जो भुगतान किया जाना था, वह उनके खातों में पहुंचने के बजाय संदिग्ध बैंक खातों में ट्रांसफर हो गया। इससे बड़ी संख्या में किसान साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसान पूरे साल मेहनत कर फसल तैयार करता है, लेकिन जब भुगतान का समय आता है तो साइबर ठग उसकी कमाई हड़प लेते हैं।

किसान सम्मान निधि पर भी उठे सवाल

कमलनाथ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में एक वर्ष के भीतर योजना से तीन लाख से अधिक किसानों के नाम हटा दिए गए हैं। उनके अनुसार वर्ष 2024-25 में जहां 86.49 लाख किसान इस योजना का लाभ ले रहे थे, वहीं 2025-26 में यह संख्या घटकर 83.01 लाख रह गई है।

सरकार ईएसबी और पीएससी के भर्ती नियमों में करेगी बदलाव

एजेंसियों के लिए ड्राफ्ट तैयार, 5 जून तक लिए जाएंगे सुझाव

भोपाल , दोपहर मेट्रो

राज्य सरकार प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती करने वाली दो एजेंसियों के भर्ती नियमों में बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए मप्र लोक सेवा आयोग और मप्र कर्मचारी चयन मंडल के भर्ती नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया है और पांच जून से इसको लेकर प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे हैं।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार अब मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर सभी सरकारी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) के माध्यम से होंगी। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और 2013 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। सरकार ने 5 जून 2026 तक आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। नियमों में बदलाव के लिए तैयार ड्राफ्ट में कहा गया है कि अब भर्ती प्रक्रिया ÷पात्रता परीक्षा÷ और ÷स्कोर कार्ड सिस्टम÷ पर आधारित होगी। ईएसबी हर साल तीन प्रकार की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा जो सामान्य पात्रता परीक्षा, तकनीकी पात्रता परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा के रूप में होंगी। पात्रता परीक्षा में तय न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए किया जा सकेगा। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड रिजल्ट जारी होने वाले वर्ष के बाद अगले दो वर्षों की 31 दिसंबर तक वैध रहेगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जीवनभर पात्र माने जाएंगे।

कई भर्तियों में आवेदन

नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को बार-बार प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। एक बार अच्छा स्कोर आने पर उसी स्कोर कार्ड के आधार पर कई विभागों की भर्तियों में आवेदन किया जा सकेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने का दावा किया गया है। सामान्य पात्रता परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जिन्हें चार हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान एवं योजनाएं, गणित, तार्किक क्षमता, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे।

मप्र की सरकारी यूनिवर्सिटीज में अब होगा डिजिटल मूल्यांकन

भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकारी विश्वविद्यालयों में अब परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने और मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालयों की परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर सहमति बनी।

विभाग का मानना है कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू होने से परीक्षा परिणामों में देरी कम होगी और विद्यार्थियों को समय पर अंकसूची व परिणाम मिल सकेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक व्यवस्थित किया जाएगा। इसके लिए एक डिजिटल असेसमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन किया जा सकेगा।

पारदर्शिता-कार्यकुशलता को बढ़ाने पर फोकस

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले सत्र में कई विश्वविद्यालयों में परीक्षा परिणाम जारी होने में देरी हुई थी। इसे देखते हुए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है, ताकि परीक्षाओं से जुड़े सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जा सकें। नई प्रणाली लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनने की उम्मीद है।

दोपहर मेट्रो | बिजली विभाग का अजब कारनामा, कोर्ट ने सिखाया सबक

14 साल पहले बंद कनेक्शन का थमाया 1.29 लाख का बिल

गुना, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियां अक्सर अपने अजीबोगरीब और भारी-भरकम बिलों के लिए सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन गुना जिले में जो मामला सामने आया है, उसने लापरवाही की सारी हदें पार कर दीं। कुंभराज (वार्ड 6) के रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग हरिशंकर शर्मा को बिजली कंपनी ने एक ऐसा करंट दिया कि उनके होश उड़ गए। कंपनी ने उन्हें एक ऐसे बिजली कनेक्शन का 1,29,931 रुपये का बिल थमा दिया, जिसे वे पूरे 14 साल पहले ही सरकारी कागजों में स्थाई रूप से बंद करा चुके थे।

साल 2010 में चुकाए थे 4,078 रुपये, फिर शुरू हुआ खेल- बुजुर्ग हरिशंकर ने सालों पहले अपने खेत के कुएं पर सिंचाई के लिए कृषि पंप का कनेक्शन लिया था।

कनेक्शन बंद: मार्च 2010 में कुआं पूरी तरह सूख गया। हरिशंकर ने ईमानदारी दिखाते हुए 24 मार्च 2010 को विभाग में आवेदन दिया और उस समय का पूरा बकाया 4,078 रुपये जमा करके कनेक्शन स्थाई रूप से कटवा लिया।

12 साल बाद पहला झटका: बिजली कंपनी के दफ्तर में यह फाइल धूल खाती रही और ठीक 12 साल बाद यानी साल 2022 में अचानक विभाग जागा। बुजुर्ग के हाथ में 92,907 रुपये का बिल थमा दिया गया। हरिशंकर ने आपत्ति जताई, तो अफसरों ने सुधार का आश्वासन देकर टाल दिया।

14 साल बाद फिर दे दिया बिल : हद तो तब हो गई जब साल 2024 में कंपनी ने इस राशि को और बढ़ाकर 1,29,931 रुपये कर दिया। परेशान बुजुर्ग ने अप्रैल 2024 में फिर गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, तो वे अपने एडवोकेट डॉ. पुष्पराग शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की शरण में चले गए।

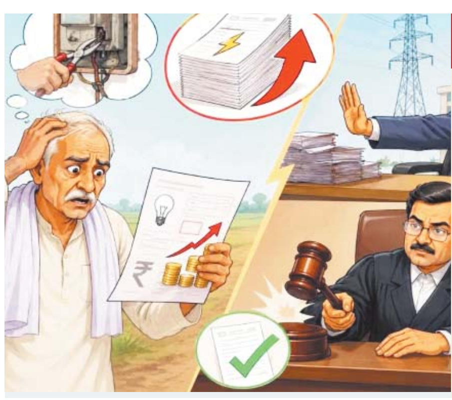

आयोग ने सुनाया तगड़ा फैसला

जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी द्वारा वर्तमान तक जारी विद्युत देयक निरस्त कर दिए। आवेदक अपने अधिवक्ता डॉ. पुष्पराग शर्मा के माध्यम से अनावेदक कनिष्ठ यंत्री मप्र विद्युत मंडल पोस्ट मृगवास तहसील कुंभराज और महाप्रबंधक मप्र विद्युत मंडल गुना के विरुद्ध उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में परिवाद पेश किया था। आयोग के अध्यक्ष सुरेशकुमार चौबे एवं सदस्य शबाना अली ने इस एकतरफा लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए उपभोक्ता के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया।

1. **सारे बिल निरस्त:** आयोग ने 24 मार्च 2010 से लेकर आज तक जारी किए गए इस कनेक्शन के सभी बिलों को तत्काल प्रभाव से शून्य (निरस्त) कर दिया।
2. **भविष्य में नो डिमांड** कंपनी को सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस बुजुर्ग कोई भी राशि न मांगी जाए।
3. **दो महीने की मोहलत:** आदेश की तारीख से 2 महीने के भीतर कागजों पर इस कनेक्शन को परमानेंट बंद दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले के बाद पीड़ित बुजुर्ग ने राहत की सांस ली है, वहीं यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे सरकारी विभाग बंद हो चुके कनेक्शन में भी बिल फूंककर वसूली की तैयारी कर लेते हैं।

आंदोलन नहीं, रास्ता तलाशना होगा

ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर भारत में 12 लाख से ज्यादा दवा विक्रेताओं ने एक दिन की हड़ताल की। यह हड़ताल मुख्य रूप से ऑनलाइन फार्मेसी (ई-फार्मेसी) प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ थी। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कॉरपोरेट घराने दवाओं पर भारी छूट देकर छोटे दुकानदारों के व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

आरोप यह भी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं बेची जाती हैं, जो मरीजों की सेहत के लिए हानिकारक है। उन सरकारी प्रावधानों का भी विरोध किया जा रहा है जिससे कि ऑनलाइन ई-फार्मेसी (ई-फार्मेसी) को बढ़ावा मिल रहा है। दवा विक्रेताओं के संगठन का आशय कुछ ऐसा है कि दवाइयों की बिक्री ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है? यह जमाना ऑनलाइन का है और कोई ऐसा कानून नहीं है जो दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगा सके। बल्कि सवाल यह है कि ऑनलाइन फार्मेसी का चलन बढ़ क्यों रहा है? मुख्य कारण यह है कि दवाइयां अंकित मूल्य से 18 से 20 प्रतिशत से भी कम कीमत पर मिल रही हैं। जब किसी व्यक्ति को घर बैठे बाजार से बीस प्रतिशत कम कीमत पर दवा मिल जाएगी तो वह बाहर क्यों भटकेगा? और ये कंपनियां यदि इतनी छूट दे रही हैं तो यह भी समझने वाली बात है कि वे घाटे में तो दवाइयां बेच नहीं रही होंगी! कुछ न कुछ मुनाफा कमा ही रही होंगी। बात इतनी ही नहीं है, यदि बाजार में कोई आपका परिचित दुकानदार है तो संभव है कि दस प्रतिशत की छूट आपको वह वैसे ही दे दे। यानी दवाइयों के पैकेट पर जो कीमत लिखी होती है, उसकी वास्तविक कीमत इतनी कम होती है कि बेचने वाला दस-बीस प्रतिशत की छूट यूं ही दे दे! स्वाभाविक तौर पर खरीदने वाला यह देखेगा कि उसे कहां कम कीमत देनी पड़ रही है। दूसरा सवाल उठाया गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं बेची जाती हैं।

देखिए, दवाएं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी दुकान पर भी बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं बेची जानी चाहिए लेकिन हम सब जानते हैं कि हालात क्या हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसे मुख्य मसला कीमत को लेकर ही है। दुकानदारों का मुनाफा कम हो रहा है इसलिए वे आंदोलन कर रहे हैं। वैसे इस आंदोलन से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि दुकानदारों को वो रास्ते तलाशने होंगे जिससे कि ग्राहक ऑनलाइन खरीदी न करे बल्कि उनकी दुकान पर आए! थोड़ा कम मुनाफा ही यह रास्ता हो सकता है।

इस मामले में सरकार को भी कुछ करना होगा। यह सोचना बहुत जरूरी है कि एक ही दवा की कीमत विभिन्न कंपनियां अलग-अलग क्यों रखती हैं? और इतनी ज्यादा कीमत क्यों प्रिंट करती हैं कि कोई उस पर बीस प्रतिशत की छूट दे पाए? निश्चय ही मामला घालमेल का है।

स्वस्थ बनने का संकल्प हो रहा साकार, बदल रही है बच्चों और माताओं की स्वास्थ्य तस्वीर

डॉ. निवेदिता शर्मा
मप्र बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष

जब किसी देश में नवजात शिशु सुरक्षित जन्म लेने लगे, माताएँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ पाने लगें, बच्चों तक समय पर टीकाकरण और पोषण पहुँचने लगे, तब समझना चाहिए कि विकास जमीन पर दिखाई देने लगा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, उसने स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तस्वीर बदल दी है। गांवों की आंगनबाड़ी से लेकर आधुनिक डिजिटल हेल्थ सिस्टम तक, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है।

स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डाजी ने महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए जिस विश्वास के साथ भारत की उपलब्धियाँ दुनिया के सामने रखीं, वह इस बदलाव का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया, वहीं मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव समेत विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इसे धरातल पर उतारने का काम किया। परिणामस्वरूप आज भारत बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया के सामने एक मजबूत उदाहरण बनकर उभर रहा है। भारत वर्ष 2005 से पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ यानी पीएमएनसीएच से जुड़ा हुआ है। आज भारत इस संगठन में बोर्ड का उपाध्यक्ष और स्थायी समिति का अध्यक्ष है। हर वर्ष 20 लाख डॉलर की स्थायी अनुदान राशि देकर भारत ने यह संदेश दिया है कि वह सिर्फ अपने देश तक सीमित न रहकर वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं, भारत ने दुनिया को यह दिखाया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाई जा सकती हैं। मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में आयुष्मान भारत योजना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस योजना ने गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए इलाज की चिंता काफी हद तक कम की है। लाखों बच्चों को गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा मिली है। देशभर में स्थापित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अब उपचार देने के साथ ही बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण का मजबूत आधार बन चुके हैं। यहाँ टीकाकरण, पोषण जांच, एनीमिया नियंत्रण और प्राथमिक उपचार जैसी सेवाएँ लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारत में बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण लंबे समय तक टीकाकरण का अभाव रहा। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष को मिशन मोड में लागू किया। इस अभियान ने दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों तक टीकाकरण सेवाएँ पहुँचाने में बड़ी सफलता हासिल की। यहां तक कि कोविड महामारी के दौरान भी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावित नहीं होने दिया गया। डिजिटल ट्रैकिंग और जमीनी स्तर पर आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयासों ने इस अभियान को नई ताकत दी। यही वजह है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

पोषण अभियान से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई: भारत में कुपोषण एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य चुनौती रही है। इसे दूर करने के लिए शुरू किया गया पोषण अभियान अब जनआंदोलन का रूप ले चुका है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। स्कूलों में मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार वितरण व्यवस्था को मजबूत किया गया है। 'पोषण पखवाड़ा' और 'पोषण माह' जैसे कार्यक्रमों ने लोगों को जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई मंचों से कुपोषण मुक्त भारत का आह्वान कर चुके हैं।

किशोर स्वास्थ्य पर बढ़ा फोकस: भारत उन शुरुआती देशों में शामिल रहा जिसने किशोर स्वास्थ्य को लेकर अलग राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 2014 में आरंभ हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों के जरिए युवाओं तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाई गईं। आज किशोरों में मानसिक तनाव, एनीमिया और जीवनशैली संबंधी बीमारियों की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे समय में सरकार का यह प्रयास भविष्य की पीढ़ी को स्वस्थ और जागरूक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवजी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य को लेकर विशेष अभियान चला रही है। राज्य में कुपोषण के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है और बच्चों की स्वास्थ्य निगरानी को डिजिटल माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की संख्या बढ़ाई है। जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात शिशु देखभाल इकाइयों का विस्तार किया गया है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार देखने को मिला है।

पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचती स्वास्थ्य सेवाएँ: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामीजी की सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का उपयोग बढ़ाया है। इससे दूर-दराज़ क्षेत्रों के बच्चों को समय पर इलाज मिल पा रहा है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। कहीं पोषण पर जोर है तो कहीं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर। इन प्रयासों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है।

यही कारण है कि आज भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करने वाले राष्ट्र के रूप में भी बनने लगी है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट, टीकाकरण कवरेज में वृद्धि और पोषण सुधार जैसे संकेतक इस बदलाव की पुष्टि करते हैं। निश्चित ही केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों ने यह साबित किया है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत हो तो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकता है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

मंदिरों का उत्थान जरूरी, साथ ही देश का सामरिक, सामाजिक और आर्थिक उद्धार भी अहम्

मुनीष त्रिपाठी
स्तंभकार

अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण लंबी न्यायिक प्रक्रिया और संघर्ष के बाद संभव हुआ। बीते 15 मई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी धार में ज्ञान की अधिष्टाती देवी सरस्वती के प्राचीन मंदिर होने का निर्णय सुनाया। साथ ही हिंदुओं के सर्व अधिकार का निर्णय देकर मुस्लिम पक्ष के मजहबी अधिकारों को खारिज कर दिया। इस मंदिर का निर्माण ज्ञानी, साहित्य प्रेमी राजा भोज ने सन 1034 में करवाया था। साथ ही परिसर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। बाद में दिल्ली सल्तनत के क्रूर हिंदू विरोधी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लामिक वर्चस्वता के कारण इस मंदिर को ध्वंस करवा दिया। बाद में यहां परवर्ती मुस्लिम शासकों ने एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करवा दिया ।

बीते कुछ दशकों से हिंदू, यहां वाग्देवी सरस्वती के मंदिर होने का दावा बता रहे थे। उन्हें बड़े जनआंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया द्वारा पूजा का अधिकार बीते वर्षों में मिला था। परन्तु पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था। मंदिर पक्ष के अधिवक्ता पिता पुत्र हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन है। ये दोनों अधिवक्ता, देश भर के काशी, मथुरा सहित दर्जनों हिंदुओं के प्रमुख दावों वाले विवादित धर्म स्थलों की पैरवी कर रहे है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिन पर मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। लगभग सभी की पैरवी ये पिता पुत्र अधिवक्ता ही कर रहे है। उनका कहना है कि भारत में ऐसे सैकड़ों हिंदू मंदिर थे जिन पर ताकत और सत्ता के कारण मस्जिदें बना ली गई है। उन सबकी मुक्ति वह न्यायिक प्रक्रिया द्वारा निकट भविष्य में करवाएंगे। यह सही है भारत में मंदिर आस्था के ही नहीं विद्या, संस्कार, शिक्षा, चेतना के केंद्र भी रहे है। दक्षिण भारत में चोल, पल्लव तथा विजयनगर प्राचीन साम्राज्य में तो मंदिर प्रशासन, राज्य और अर्थव्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसलिए इनका पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण आवश्यक है। परंतु उससे भी ज्यादा आवश्यकता भारतीय, राष्ट्रीय समाज की सुरक्षा व्यवस्था की है।

भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जहां विविध पंथिक , सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं सहस्त्राब्दियों से साथ-साथ विकसित हुई हैं। हिंदू समाज ने भारतीय संस्कृति, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, कला और राष्ट्रीय जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। वर्तमान समय में देश में अनेक धार्मिक स्थलों, सांस्कृतिक विरासतों तथा ऐतिहासिक विवादों को लेकर न्यायिक और सामाजिक स्तर पर विमर्श चल रहा है। ऐसे समय में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि केवल मंदिरों या धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर्याप्त है या उससे अधिक आवश्यक एक सशक्त, शिक्षित, संगठित और आत्मविश्वासी समाज का निर्माण है। वास्तव में किसी भी सभ्यता की स्थायी सुरक्षा उसके सामाजिक आधार की मजबूती पर निर्भर करती है। अतः हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक, वैचारिक, सामरिक और राष्ट्रीय आयामों से जुड़ा हुआ विषय है। वैश्विक कट्टर मुस्लिम जगत के लोग,पीएफआई जैसे कई संगठन भारत को दारुल हरब मानकर, दारुल इस्लाम बनाने का मंसूबा पाले हुए है जो आये दिन हिंसक, विध्वंसक वारदातें करते रहते है। भारतीय सरकार के साथ साथ, भारतीय समाज को भी चौकन्ना होकर मुकाबला करना होगा। किसी भी समाज की शक्ति उसकी सांस्कृतिक स्मृति में निहित होती है। हिंदू समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अपनी परंपराओं, ग्रंथों, महापुरुषों और इतिहास के प्रति जागरूकता का अभाव है। यदि समाज अपनी जड़ों से कट जाता है, तो वह बाहरी वैचारिक दबावों के प्रति अधिक प्रभावित हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि भारतीय इतिहास को संतुलित और प्रमाणिक दृष्टि से समझा जाए। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भारतीय दर्शन, वेदांत, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भक्ति आंदोलन, संत परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू समाज के योगदान का अध्ययन बढ़ाया जाना चाहिए। सांस्कृतिक गौरव का अर्थ किसी अन्य समुदाय के प्रति विरोध नहीं, बल्कि अपनी पहचान और परंपरा के प्रति आत्मविश्वास होना चाहिए। स्वाधीनता के पहले और बाद में भी हिंदू,धार्मिक जानलेवा हमले, धर्मान्तरण, जनसंख्या असुन्तलन, अवैध घुसपैठिये जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसका तत्काल समाधान होना आवश्यक है। आज का युग ज्ञान और सूचना का युग है। यदि कोई समशिक्षा, अनुसंधान और बौद्धिक नेतृत्व में पिछड़ जाता है तो वह दीर्घकाल में कमजोर हो जाता है। हिंदू समाज की सुरक्षा केवल भावनात्मक नारों से नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और वैचारिक स्पष्टता से सुनिश्चित होगी। उच्च शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और अकादमिक जगत में अधिकाधिक उच्च संस्कारित प्रतिनिधित्व आवश्यक है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधुनिक शोध को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, आयुर्वेद, योग और पारंपरिक ज्ञान-विज्ञान को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करना समय की आवश्यकता है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया और इंटरनेट वैचारिक संघर्ष के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। इसलिए युवाओं को तथ्यपरक अध्ययन, तार्किक संवाद और संवैधानिक मूल्यों के साथ अपनी बात रखने का प्रशिक्षण भी आवश्यक है जिससे देशभक्त बौद्धिक योद्धाओं का निर्माण हो सके। किसी भी समाज की स्थिरता उसके आर्थिक आधार पर निर्भर करती है। आर्थिक रूप से कमजोर समाज दीर्घकाल में अपनी सांस्कृतिक संस्थाओं और शैक्षिक संरचनाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए हिंदू समाज के व्यापक वर्गों में उद्यमिता, कौशल विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना आवश्यक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग, पारंपरिक कारीगरी, कृषि और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने से समाज की सामूहिक शक्ति बढ़ेगी।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अलर्ट

पेट फूलना भी ओवरी कैंसर का संकेत हो सकता है, संकेतों को न करें नजरअंदाज

हार्मोनल बदलाव के कारण महिलाओं के शरीर में कई बदलाव होते रहते हैं। ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या भी इसी में से एक है। कभी कभार ऐसा होना नॉर्मल है। गैस, हार्मोनल बदलाव या पीरियड्स के कारण ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। लेकिन लंबे समय तक यह समस्या बनी रहे, तो ये नॉर्मल नहीं है। महिलाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि लगातार पेट फूलना कई बार अंडाशय यानी ओवरी के कैंसर का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। हर बार पेट फूलना कैंसर का संकेत नहीं होता, लेकिन यदि यह समस्या कई दिनों या हफ्तों तक बनी रहे, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी हो जाता है।

ब्लोटिंग के दौरान लगातार पेट फूलने के साथ शरीर में कुछ और लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे- पेट या पेल्विक एरिया में दर्द,पेट भारी लगना, भूख कम लगना, थोड़ा खाने पर पेट भर जाना, बेवजह वजन बढ़ना या घटना, बार-बार पेशाब आना,कब्ज और थकान। ब्लोटिंग के दौरान महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलावों के लक्षण शुरुआत में हल्के लगते हैं, इसलिए महिलाएं इन्हें गंभीरता से नहीं लेतीं।

किन महिलाओं को खतरा ?: कुछ महिलाओं में ओवरी कैंसर का खतरा ज्यादा हो सकता है। जिन महिलाओं के परिवार में ओवरी, ब्रेस्ट या कोलोरेक्टल कैंसर का इतिहास रहा हो, उनमें जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र, मोटापा, सिगरेट की लत, एंडोमेट्रियोसिस और कुछ आनुवंशिक बदलाव भी खतरा बढ़ा सकते हैं। जिन महिलाओं के परिवार में कैंसर का इतिहास नहीं है, उन्हें भी यह बीमारी हो सकती है इसलिए हर महिला को जागरूक रहना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि ओवरी कैंसर सिर्फ अधिक उम्र की महिलाओं को होता है। यह पूरी तरह सही नहीं है। हालांकि मेनोपॉज के बाद इसका खतरा बढ़ जाता है, लेकिन युवा महिलाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। उम्र के कारण लक्षणों को नजरअंदाज करना कभी-कभी बीमारी को गंभीर बना सकता है।

सेहत के प्रति जागरूक रहें: महिलाओं को अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स पर खुलकर बात करनी चाहिए। कई बार शर्म या डर की वजह से महिलाएं लक्षणों को छिपाती हैं। लेकिन शरीर के संकेतों को समझना और समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी है। पेट फूलना एक छोटी समस्या लग सकती है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बनी रहे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। शरीर अक्सर बड़ी बीमारी आने से पहले छोटे संकेत देता है। इन संकेतों को समय रहते पहचानना और सही कदम उठाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।

निशाना

नारों की यह झोली कब तक..!

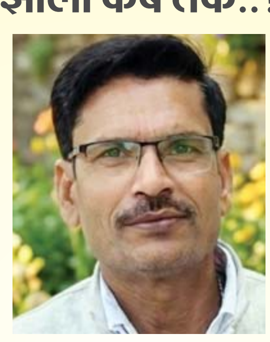

मनोज साहू 'निडर'

अब ये टालमटोली कब तक
खुद सेऑख मिचौली कब तक
दिल में क्या है पता है सबको
चेहरे पर रांगोली कब तक
झूठों के सम्मान की खातिर
सच की नंगाझोली कब तक
ख्वाब मुखौटे धोखेबाजी
सत्ता की हमजोली कब तक
जन सेवा का बाना ओढ़े
मक्कारों की टोली कब तक
रोटी कपड़ा शिक्षा रोज़ी
नारों की ये झोली।कब तक
जनमन को भरमाकर आखिर
ये बदरंग ठिठोली, कब तक ।

यूजर्स गाइड

आग लगने का खतरा , एक्सटेंशन बोर्ड की लोड क्षमता जानकार ही करें इस्तेमाल

एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल घर-घर में होता है लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अगर एक्सटेंशन बोर्ड पर जरूरत से ज्यादा लोड डाल दिया जाए, तो शॉर्ट सर्किट होने के साथ-साथ आग लगने का भी खतरा बना रहता है। यही वजह है कि पावर कारपोरेशन की ओर से पोस्ट कर ज्यादा प्लग एक्सटेंशन बोर्ड में न लगाने की सलाह दी है। किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड में कम से कम तीन से चार प्लग लगाने की जगह होती है। हालांकि, सुरक्षा के लिए इस बात पर गौर करने की जरूरत नहीं है कि बोर्ड में कितने प्लग लगे हैं बल्कि सारा खेल इस बात का है कि बोर्ड पर कितना लोड डाला जा रहा है। एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल करते हुए उसकी कुल एम्पियर क्षमता और उपकरणों के वाट का ध्यान रखना जरूरी होता है।

आसान शब्दों में कहें तो, आप कम बिजली खाने वाले 4 उपकरण तो एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन भारी लोड वाला सिर्फ एक ही उपकरण पूरे बोर्ड को फूंकने के लिए काफी होता है। ऐसे में ध्यान लोड पर होना चाहिए, कितने प्लग लगे हैं उस पर नहीं। किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड को खरीदते समय इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि वह कितना लोड या कहें कि वाट झेल सकता है। घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य एक्सटेंशन बोर्ड अधिकतम 1000W से 1500W तक का भार संभाल सकते हैं। ऐसे में अगर आप बोर्ड पर मोबाइल चार्जर, लैपटॉप या टीवी जैसे कम बिजली खाने वाले 4 उपकरण भी एक साथ प्लग कर दें, तो कुल लोड मुश्किल से 200W-300W होगा। इतने लोड को कोई भी बोर्ड आराम से झेल सकता है।

हैवी अप्लायंस दूर रखें: एक्सटेंशन बोर्ड से हैवी अप्लायंस दूर रखने चाहिए। उदारहरण के लिए एक इलेक्ट्रिक केतली का लोड 1500W, गीजर 2000W तक लोड खींचता है। इसी तरह रूम हीटर वाशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव और प्रेस भी ज्यादा बिजली खींचते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल करने से पहले बोर्ड के पीछे या उसके बॉक्स पर लिखी रेटिंग को जरूर पढ़ें। गौर करने वाली बात है कि वोल्ट और एम्पियर को गुणा करने पर कुल वाट क्षमता निकलती है। भारत में 220V की सप्लाई होती है, यानी 6A का बोर्ड करीब 1320 वाट तक का ही लोड ले सकता है। जब आप इस क्षमता से वाकिफ होते हैं, तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस उपकरण को साथ में प्लग करना है और किसे नहीं। सरकारी सलाह भी यही कहती है कि सतर्क रहें, उपकरणों के वाट को जोड़ें और बोर्ड को उसकी लिमिट से आधा ही लोड दें।

नेचर वॉच

सबसे मोटी चमड़ी वाला जानवर, प्रकृति ने पहनाया है 'स्वेटर', बर्फीली हवा भी बेअसर

साइबेरिया की बर्फीली वादियों में जहां इंसान भी कुछ मिनटों में ठिठुर कर रह जाता है, वहां एक जानवर राज करता है। माइनस 40 डिग्री से भी ज्यादा ठंड में ये बेफिक्र घूमता फिरता है। बर्फीली हवाएं इसके शरीर को छू भी नहीं पाती. ये है साइबेरियन बाघ, जिसे अमूर टाइगर भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक बिल्लियों में शुमार ये प्रजाति प्रकृति का कमाल है। साइबेरियन बाघ की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मोटी चमड़ी और उसके नीचे मौजूद चर्बी की मोटी परत। सामान्य बाघों की तुलना में इनकी फर (फर को लोक भाषा में चमड़ी कहा जाता है) बहुत घनी और लंबी होती है। सर्दियों में ये फर और भी मोटा हो जाता है। गर्दन के चारों ओर बालों की परत इसे ठंड से बचाती है।

कुदरत का करिश्मा: वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी सर्दियों वाली फर गर्मियों वाली फर से दोगुनी मोटी हो सकती है। इसके अलावा शरीर पर चर्बी की मोटी परत इंसुलेशन का काम करती है जो शरीर की गर्मी को अंदर रखती है। ये बाघ 300 किलो तक वजन का हो सकता है। नर बाघ औसतन 176 से 222 किलो तक होते हैं जबकि कुछ बड़े नमूने 300 किलो से ज्यादा भी पाए गए हैं। इनकी लंबाई पूंछ समेत 3 मीटर से ज्यादा हो सकती है। इतना भारी-भरकम शरीर होने के बावजूद ये बर्फ पर हल्के कदमों से चलता है। इसके बड़े-बड़े पंजों पर घनी बालों की परत होती है जो स्नोशू की तरह काम करती है। इससे ये बर्फ में धंसता नहीं और चुपके से शिकार के पास पहुंच जाता है।

बेहतरीन शिकारी: साइबेरियन बाघ का शिकार करना भी कमाल का है। ये अकेला शिकारी है, जो जंगलों में घंटों इंतजार करता है और फिर एक झपट्टे में 200-300 किलो के हिरण या वाइल्ड बोअर को गिरा देता है। माइनस तापमान में भी इसकी ताकत और फुर्ती कम नहीं होती। ठंड के कारण शिकार कम मिलने पर ये कई दिनों तक भूखा रह सकता है। चर्बी की परत इसमें मदद करती है, ये बाघ मुख्य रूप से रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों, चीन और उत्तर कोरिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इनका प्राकृतिक निवास ताइगा जंगल है जहां बर्फ साल भर रहती है। यहां का तापमान अक्सर माइनस 40 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसी स्थिति में दूसरे जानवर ठंड से मर सकते हैं लेकिन साइबेरियन बाघ आराम से घूमता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार साइबेरियन बाघ की फर अन्य बाघ प्रजातियों से सबसे मोटी होती है। बाल लंबे और घने होते हैं जो हवा को अंदर नहीं जाने देते। पंजों पर बाल पैरों को गर्म रखते हैं और फ्रॉस्टबाइट से बचाते ह। ये अनुकूलन इसे दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं।

न्यूज विंडो

रिपटा घाट पर तीन दिवसीय तैराकी एवं बोट हैंडलिंग प्रशिक्षण शुरू

गंजबासौदा। मुख्यालय एवं जिला कमांडेंट के निर्देशानुसार बेतवा नदी स्थित रिपटा घाट पर तीन दिवसीय तैराकी एवं बोट हैंडलिंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे होमगार्ड जवान भाग लेकर जल बचाव एवं आपदा प्रबंधन की बारीकियां सीख रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान जवानों को नदी में सुरक्षित तैराकी, डूबते व्यक्ति को बचाने की तकनीक, बोट संचालन, रस्सी एवं लाइफ जैकेट के उपयोग सहित आपदा के समय त्वरित राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी दी जा रही है। विदिशा से आए एएसआई लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा एवं एसडीआरएफ जवानों द्वारा जवानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों ने बताया कि बरसात के मौसम में नदी-नालों में बढ़ते जलस्तर के दौरान ऐसी ट्रेनिंग जीवन रक्षक साबित होती है। प्रशिक्षण शिविर में जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए जल आपदा से निपटने के आधुनिक तरीकों का अभ्यास किया। आयोजन का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में होमगार्ड जवानों को दक्ष एवं सक्षम बनाना है।

भीषण गर्मी में चलाया दाना-पानी अभियान, प्यासे पक्षियों को मिला सहारा

गंजबासौदा। कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीषण गर्मी में पक्षियों के संरक्षण एवं उनके लिए भोजन-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दाना-पानी अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर सकोरे रखकर उनमें दाना और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की, जिससे गौरैया सहित अन्य पक्षियों को राहत मिल सके। इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण, जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता और करुणा की भावना को बढ़ावा मिला। अभियान ने यह संदेश दिया कि छोटी-छोटी पहलें मिलकर बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। स्वयंसेवकों ने केवल पात्र स्थापित ही नहीं किए, बल्कि उनकी नियमित सफाई एवं प्रतिदिन दाना पानी भरने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम जिला संगठक डॉ. प्रवीण कुमार जगा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। अभियान में एनएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक भरत सक्सेना, विवेक जोशी सहित अन्य स्वयंसेवकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विनोद कुमार गर्ग ने छात्रों के इस सराहनीय प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी ऐसे जन-जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण अभियानों को निरंतर जारी रखने के लिए शुभकामनाएं दीं।

पेट्रोल पंप के सामने खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

गंजबासौदा। ग्राम बरेठ में स्लीपर फैक्ट्री के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने खड़े ट्रक में शुक्रवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ट्रक से काला धुआं और आग की ऊंची लपटें उठने लगीं, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार ट्रक रात से ही पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था। सुबह अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में आग ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। पेट्रोल पंप के नजदीक आग लगने से बड़े हादसे की आशंका बन गई थी। घटना के दौरान ट्रक चालक और क्लीनर वाहन के अंदर सो रहे थे। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि आग तेजी से फैलती चली गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। घटना के कारण कुछ देर तक क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

लीगेसी वेस्ट निष्पादन मामले में डिप्टी कलेक्टर ने शिकायतकर्ता के साथ डंप यार्ड का किया निरीक्षण

जांच अधिकारी ने एमआरएफ के संचालन, विभाजन की प्रक्रिया और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था देखी

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

लीगेसी वेस्ट से जुड़े निष्पादन मामलों में कलेक्टर जनसुवाई मे हुई शिकायत के बाद गुरुवार को नर्मदापुरम से इटारसी पहुंचे डिप्टी कलेक्टर (परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास प्राधिकरण) देवेंद्र प्रताप सिंह ने पथरोटा स्थित जिलवानी कचरा प्रबंधन साइटों का निरीक्षण किया। वे दोपहर करीब 12 बजे नगर पालिका कार्यालय पहुँचे जहां उन्होंने पहले सीएमओ कक्ष में सीएमओ सहित संबंधित अधिकारियों से मामले की फाइलें और जानकारी तलब की। करीब 15-20 मिनट की चर्चा के बाद डिप्टी कलेक्टर, शिकायतकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट अमोल उपाध्याय और कांग्रेस नेता राजेंद्र तोमर के साथ पथरोटा स्थित जिलवानी के लिए रवाना हो गये। इस दौरान सीएमओ रितु मेहरा, एई मीनाक्षी चौधरी, उपयंत्री मोनिका अग्रवाल और उपयंत्री मयंक अरोरा भी साथ रहे।

जिलवानी में डिप्टी कलेक्टर ने सबसे पहले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर का निरीक्षण किया। जांच अधिकारी ने एमआरएफ के संचालन, विभाजन प्रक्रियाओं और कचरा प्रबंधन कि व्यवस्था देखी । इसके बाद कुछ कदम की दूरी पर स्थित डंप यार्ड का भी जायजा लिया । इस दौरान एमआरएफ से जांच अधिकारी, शिकायतकर्ता के साथ पैदल ही डंप यार्ड में लगे कचरे के ढेरों तक पहुँच गए,जबकि चंद कदमो की दूरी तक नगर पालिका की तीनों महिला अधिकारी को चार

पहिया वाहन का सहारा लेना पड़ा ।

शिकायतकर्ता अमोल उपाध्याय ने निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर एवं जांच अधिकारी को डंप यार्ड स्थल की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया और वहां फैली गंदगी, गंध तथा प्रबंधन में पाई जा रही खामियों पर अपनी आपत्तियाँ दर्ज करायीं। डिप्टी कलेक्टर नें डंप यार्ड निरीक्षण के दौरान अपने मोबाइल से कुछ फोटो भी क्लिक की है डिप्टी कलेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता अमोल उपाध्याय ने जनसुनवाई में लीगेसी वेस्ट के निष्पादन प्रक्रिया के बारे में शिकायत की थी। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैंने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर डंप यार्ड का स्थल निरीक्षण किया। स्थल निरीक्षण, अभिलेख और शिकायत के बिंदुओं का मिलान करके निष्कर्ष निकाले जाएंगे। संयुक्त जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा जाएगा।

शिकायतकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट अमोल उपाध्याय का कहना है कि हमने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माँग की है कि इस गंभीर शिकायत की स्वतंत्र और तकनीकी जांच के लिए एनजीटी एक विशेष जाँच समिति बनाए। इस समिति में एनजीटी का प्रतिनिधि, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, जल संसाधन विभाग और भूजल अधिकारी तथा ज़रूरत के अनुसार अन्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए जाएँ। समिति पूरी जाँच कर अपने निष्कर्षों सहित रिपोर्ट एनजीटी को सौंपे ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

कचरे कि गंध और धुएं से परेशना है ग्रामीण....

डंप यार्ड के पास रहने वाले ग्रामीणों ने मौक़े पर पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह से मिलकर अपनी समस्याएँ बताईं। भूतपूर्व सैनिक भीमराव ने कहा कि डंप यार्ड में कचरा जलाया जा रहा है, जिससे चारों ओर धुआँ फैल जाता है।कचरे का निस्तारण नही किया जा रहा है। यहां रोजाना लगभग 1000-1500 मवेशी घूमते हैं और धुएँ के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। भीमराव ने कहा कि नगर पालिका को यहीं तार की बाड़ या दीवार बनानी चाहिए। साथ ही नगर पालिका यहाँ मरे हुए जानवर फेंककर छोड़ जाती है और उन्हें दफन नहीं किया जाता। नलों से गंदा पानी आ रहा है, इसकी जांच कराई जाए। रामफल भल्लावी ने बताया कि डंप यार्ड से निकलने वाला नाला कुबड़ाखेड़ी गाँव तक आता है। जिस के कारण पीने का पानी गंदा आ रहा है उन्होंने कहा कि पहले भी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिप्टी कलेक्टर ने ग्रामीणों की बात सुनने के बाद कहा कि उन्होंने दूसरा पक्ष भी सुन लिया है और जल्द ही फेंसिंग की व्यवस्था करवाई जाएगी। इस दौरान भीमराव, रामफल भल्लावी, संदीप विश्वकर्मा, सुनील यादव और अन्य मौजूद थे।

स्वच्छ भारत मिशन का मजाक बना अमरकंटक

स्वच्छ पेयजल की समस्या गंभीर गंदे पानी और कचरे से जूझ रहे लोग

अमरकंटक। दोपहर मेट्रो

अमरकंटक में स्वच्छ पेयजल की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि क्षेत्र की बाबलियों, कुओं और जलस्रोतों में कचरे का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद न तो अमरकंटक विकास प्राधिकरण और न ही अमरकंटक नगर पालिका इस ओर गंभीर ध्यान दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अमरकंटक उद्गम स्थल परिसर में स्थित कुएं की हालत भी बेहद खराब हो चुकी है। कुएं के आसपास गंदगी फैली हुई है और पानी में कचरा जमा होने से बदबू तथा प्रदूषण बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि धार्मिक आस्था के केंद्र होने के बावजूद यहां सफाई व्यवस्था पूरी तरह लापरवाह नजर आती है। लोगों का आरोप है कि जिन जलस्रोतों का उपयोग आम नागरिक करते हैं, उनमें प्लास्टिक, सड़ा कचरा और गंदगी भरी पड़ी है। इतना ही नहीं, जिस पानी का उपयोग स्वयं प्रशासनिक संस्थाएं करती हैं, उसमें पुराने कपड़े और इस्तेमाल किए गए डायपर तक पड़े हुए पाए गए हैं। ऐसे हालात में लोगों का सवाल है कि आखिर अमरकंटकवासियों को स्वच्छ पानी कब मिलेगा। धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद अमरकंटक की सफाई व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। जगह-जगह फैली गंदगी, दूषित जल स्रोत और उपेक्षित कुएं स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत को उजागर कर रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग केवल कागजों में अभियान चला रहे हैं।

अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की कार्रवाई, पनडुब्बी व मोटरबोट जब्त

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण के विरुद्ध प्रशासन की कड़ी कार्रवाई जारी है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर राजस्व व खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से ग्राम पथाडा, तहसील सिवनी मालवा में छापेमारी कर अवैध रूप से रेत उत्खनन करते हुए एक पनडुब्बी व एक मोटरबोट जब्त कर लिया है। जब्त किए गए दोनों वाहनों को पुलिस थाना शिवपुर की अभिरक्षा में रखा गया है और संबंधित प्रकरण दर्ज कर आगामी वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध उत्खनन, अवैध खनिज परिवहन व भंडारण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती बरती जाए

और किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए। जिला प्रशासन ने कहा है कि अवैध खनन गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी ऐसे कड़े अभियानों को जारी रखा जाएगा ताकि प्राकृतिक संसाधनों की अवैध निकासी रोकी जा सके और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

सीएमओ ने जनसुनवाई कर समस्याओं का किया समाधान

पीएमआवास की लिस्ट में नाम जोड़ने, राशन कार्ड से नाम हटाने और नाली निर्माण की आई शिकायतें

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले द्वारा जनसुनवाई की गई। नागरिकों की छोटी छोटी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान पीएम आवास योजना की लिस्ट में नाम जोड़ने, किश्त जारी करने, समग्र आइडी सुधरवाने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नाली निर्माण संबंधी, अतिक्रमण हटाने जैसी समस्याएं आई अधिकांश आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। साथ ही जांच योग्य आवेदनों को संबंधित शाखा को भेज दिया गया। इस दौरान जन्म मृत्यु शाखा के कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही बरतने पर सीएमओ द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई। नीतेश खंडेलवाल द्वारा ग्वालटोली में अतिक्रमण शिकायत कर शीघ्र हटाने की मांग की गई। कार्यालय अधीक्षक योगेश सोनी ने बताया कि नपाध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले के मार्गदर्शन में जनकल्याण

हेतु नपा में जनसुनवाई की शुरूआत की है। जिसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लोगों को तत्काल समाधान मिल रहा है। विगत जनसुनवाई में पार्षदगणों द्वारा अपने वार्ड की समस्या बताई थी जिस पर नपाध्यक्ष श्रीमती यादव एवं सीएमओ श्रीमती पटले द्वारा संबंधित शाखा से जांच उपरांत समाधान कराया गया। वार्ड 31 के पार्षद नरेंद्र पटले ने आभार मानते हुए कहा कि हमारे वार्ड के एक मोहल्ले में पेयजल संबंधी बड़ी समस्या थी। पाइप लाइन आधी अधूरी बिछाई गई थी। उसके संबंध में आवेदन दिया था। जिसका समाधान हो गया है नई पाइप बिछ गई है। साथ ही नई सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर आभार व्यक्त किया गया। इसी तरह वार्ड 25 के पार्षद दुर्गेश चौधरी के वार्ड में स्थित पिंक एवेन्यू कालोनी के मुख्यद्वार पर तीन लाइट लगाने की मांग की गई थी जिसका भी समाधान हो गया।

कर्मचारियों को दिया नोटिस

जन्म-मृत्यु शाखा के चार कर्मचारियों द्वारा लापरवाहीपूर्वक कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से सीएमओ श्रीमती पटले द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिसमें पूजा दोहरे, ललित दोहरे, धर्मेंद्र टांक शामिल हैं तथा आउट सोर्स कर्मचारी नीलम कहार की सेवाएं समाप्त की गई। उन्होंने हिदायत दी कि जनसुनवाई में आने वाले आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई कर आवेदक को राहत प्रदान करें।

आईटीआई सोहागपुर के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त

नर्मदापुरम/सोहागपुर। दोपहर मेट्रो

क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह ने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) सोहागपुर की आईएमसी (इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी) समिति के गठन के लिए अभिनव पालीवाल एवं शुभम रघुवंशी को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्ति की जानकारी भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्वनी स्वरूप ने दी। विधायक द्वारा जारी पत्र के माध्यम से दोनों युवाओं – मातापुरा वार्ड निवासी अभिनव पालीवाल और ग्राम हीरापुर निवासी शुभम रघुवंशी – को आईटीआई के प्राचार्य को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश के साथ विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। आईएमसी समिति का उद्देश्य संस्था और उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करना, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी वातावरण उपलब्ध कराना बताया गया है। नियुक्ति के बाद दोनों प्रतिनिधियों को उनके शुभचिंतकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बधाई दी। इस अवसर पर प्रतिनिधियों के चयन पर विधायक विजयपाल सिंह ने प्रदेश एवं क्षेत्र के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

मेट्रो एंकर

सीआरपीएफ, एसएएफ से लेकर केंद्र व राज्य सरकार की खुफिया एजेंसी हुई सक्रिय

देश भक्ति के गीत बजाते हुए निकाला फ्लैग मार्च, 2200 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा

धार। दोपहर मेट्रो

हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला को मंदिर मनाने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद आज 22 मई को पहला शुक्रवार हैं, इसको लेकर धार पुलिस से लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में शांति बनाएं रखने के लिए 2200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गुरुवार दोपहर तक सभी अधिकारी धार पहुंच चुके है। शाम के समय शहर में तिरंगा लेकर पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। शुक्रवार को आने वाली बसंत पंचमी के बाद पहली बार ऐसा मौका हैं, कि धार में इतनी बडी संख्या में पुलिस बल रहेगा। राज्य शासन से लेकर केंद्र की खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, शहर की सुरक्षा को तीन लेयर में विभाजित किया गया है। जिसमें पहली लेयर भोजशाला के भीतर, दूसरी लेयर भोजशाला सहित आसपास का 50 मीटर तथा अंत में शहर की सुरक्षा को तीसरी लेयर में विभाजित किया गया है। पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम सक्रियता बढा दी गई हैं, शुक्रवार को किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर महज डेढ मिनट में बाइक पुलिस टीम गली से लेकर मोहल्ले तक पहुंच जाएगी। शहर में शांति, सुरक्षा और आपसी भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पुलिस प्रशासन द्वारा एक विशेष फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुए इस मार्च की कमान खुद पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने संभाली। फ्लैग मार्च के माध्यम से प्रशासन ने आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस के जवान हाथों में राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) थामे सबसे आगे चल रहे थे। मार्च के दौरान लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे थे, जो पूरे शहर में राष्ट्रप्रेम और अनुशासन का संदेश दे रहे थे। पुलिसबल के इस रूट मार्च को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी सचिन शर्मा शहर के प्रमुख और संवेदनशील चौराहों पर रुके। उन्होंने वहां मौजूद नागरिकों से सीधा संवाद किया और शहर में हर हाल में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। एसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। मार्च ने नगर के करीब तीन किलोमीटर लंबे मार्ग का भ्रमण किया।

महिला पुलिस बल तैनात

पुलिस अधिकारियों के अनुसार दो सीआरपीएफ, 10 एसएएफ की टीम धार पहुंच चुकी है। साथ ही दो एएसपी, 15 डीएसपी, 30 थाना प्रभारी सहित महिला बल, यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के जिलों सहित भोपाल, मंदसौर, रतलाम जिलों का पुलिस बल भी आया है। दो अश्वारोही दल भोजशाला चौकी परिसर के आसपास ही भ्रमण करते रहेंगे। बीडीएस सिस्ट म, ओपन बॉडी वाहन से लेकर लाईट मशीन गन भी सुरक्षा के चलते मौजूद रहेगी। चार ड्रोन कैमरों, 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से चप्पेई-चप्पेक पर नजर रखी कंट्रोल रूम से रखी जाएगी। पुलिस मोबाइल वाहन, बाइक पुलिस टीम भी सुबह से लेकर देर रात तक भ्रमण करती रहेगी, शहर के सभी धार्मिक स्थानों पर पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। नगर की ऊंची इमारतों से भी जवान मोहल्लों में नजर बनाए रखेंगे।

अस्थाई जेल की व्यवस्था

जेल वाहन, वज्र वाहन, फायर बिग्रेड से लेकर एंबुलेंस भी अलर्ट मोड पर हैं, प्रशासन ने गिरफ्तार पुलिस पार्टी बनाई है, जो किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत एक्टिव होगी। साथ ही अस्थाई जेल की व्यवस्था भी की गई है। जिला पुलिस प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया या किसी अन्य संचार माध्यम से भ्रामक, भड़काऊ, अप्रमाणित या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित न करें। ऐसा करने वालों पर साइबर सेल और पुलिस की कड़ी नजर है। जिला प्रशासन ने सभी समुदायों से न्यायिक प्रक्रिया और कानून व्यवस्था का सम्मान करने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून का शासन और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन ने आमजन को संदेश देते हुए कहा है कि शांति बनाए रखें अफवाहों से बचें, कानून का सम्मान करें।

अनूपपुर फ्लाईओवर: विकास का प्रतीक या भ्रष्टाचार का स्मारक?

अनूपपुर। दोपहर मेट्रो

अनूपपुर में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अब लोगों के लिए सुविधा से ज्यादा मजाक और चर्चा का विषय बन चुका है। वर्षों से अधूरा पड़ा यह फ्लाईओवर अब धीमी गति के विकास की मिसाल बन गया है। हालात ऐसे हैं कि जिस समय इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था, उस दौरान सरकारी अस्पताल में जन्मे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन पुल आज भी अधूरा ही खड़ा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे बुजुर्ग भी इस पुल को बनते हुए देखते थे और अब हमारी अगली पीढ़ी भी वही देख रही है। पुल की रफ्तार इतनी धीमी है कि कछुआ भी इसे देखकर अपनी चाल पर गर्व महसूस करे। नीचे रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें तेज रफ्तार से गुजर रही हैं, देश डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ऊपर पुल का लोहे का ढांचा वर्षों से धूप और बारिश झेलते हुए उसी स्थिति में खड़ा है। तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि आज भी लोग धूल उड़ाते हुए कच्चे रास्तों से साइकिल और दोपहिया वाहन निकालने को मजबूर हैं, जबकि ऊपर अधूरा पुल मानो लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहा हो। मौके पर काम कर रहे कुछ मजदूर भी इस विशाल ढांचे को ऐसे निहारते दिखते हैं जैसे कोई कलाकार अपनी अधूरी कलाकृति को वर्षों से पूरा करने का इंतजार कर रहा हो।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पुल निर्माण का प्रारंभिक अनुमानित बजट अब लगभग दोगुना खर्च हो चुका है, इसके बावजूद कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में भारी वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग और ठेकेदार केवल ÷कार्य प्रगति पर है÷ का बोर्ड दिखाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रहे हैं।

व्यंग्य में लोग अब कहने लगे हैं कि ताजमहल कुछ वर्षों में बन गया था, लेकिन अनूपपुर फ्लाईओवर शायद पुरातत्व विभाग द्वारा ऐतिहासिक स्मारक घोषित होने के बाद ही पूरा होगा।÷ नागरिकों ने शासन और प्रशासन से निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कर समयसीमा तय करने की मांग की है, ताकि आम जनता को वर्षों से झेल रही परेशानी से राहत मिल सके।

जनसुनवाई में आम जनों की समस्याओं से रूबरू होकर करते हैं स्थायी समाधान

नरसिंहपुर। दोपहर मेट्रो

विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल द्वारा प्रत्येक गुरुवार को विधायक निवास पर आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई में इस सप्ताह 312 आवेदन प्राप्त हुए। अपने-अपने प्रकरण लेकर पहुंचे आमजन की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए पटेल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया जनता और जनप्रतिनिधि के बीच संवाद का यह सशक्त मंच ग्रामीण अंचलों के लोगों के लिए बड़ी उम्मीद बन चुका है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर बिना किसी हिचक के पहुंचते हैं और उनके त्वरित निराकरण से संतुष्ट होकर वापस लौटते हैं। यही विश्वास और भरोसा जालम सिंह पटेल को जनता की पहली पसंद बनाता है राजनीति में प्रवेश से पहले सामाजिक सेवा को प्राथमिकता देने वाले जालम सिंह पटेल आज भी स्वयं को नेता नहीं, बल्कि जनता का बेटा मानते हुए हर वर्ग के हितों की लड़ाई में आगे रहते हैं। जनसुनवाई के माध्यम से लगातार हो रहे समाधान ने क्षेत्रवासियों में यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि उनकी समस्याओं के समाधान हेतु उनका जनसेवक सदैव तत्पर खड़ा है। उक्त जानकारी देते हुए विधायक मीडिया प्रभारी वैभव नेमा ने बताया कि जनसुनवाई में 312 आवेदनों की प्राप्ति हुई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी गणमान्य नागरिक सहित अनेक समाजसेवी जन मौजूद रहे।

तीन दिन तक चलेगी ग्रीष्मकालीन गिनती तेंदूखेड़ा के उप वनमंडल में सबसे ज्यादा है संख्या

आज से शुरू होगी गिद्ध गणना, वन विभाग खोजेगा घोंसले, पेड़ पर बैठे हुए गिनेंगे

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

वन विभाग के द्वारा आज से ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना आज 22 से 24 मई तक कराई जा रही है। इसमें वन विभाग का अमला गिद्ध आवास खोजेंगे। वन विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। इसको देखते हुए वन विभाग के द्वारा गिद्ध संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हर साल शीतकालीन और ग्रीष्म कालीन गिद्ध गणना कराई जा रही है। शीत कालीन गिद्ध गणना 20 से 22 फरवरी तक की गई थी अब 22 से 24 मई तक ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना की जा रही है।

गिद्ध गणना का कार्य गिद्ध आंकलन एवं संरक्षण के लिए विकसित उन्नत डिजिटल मोबाइल एप गरुण के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही प्रचलित प्रपत्रों के माध्यम से भी फील्ड स्टाफ द्वारा निर्धारित तिथियों में डाटा प्रविष्टि का कार्य किया जाएगा। गिद्ध गणना के लिए प्रशिक्षित मैदानी अमला सुबह पांच बजे चिन्हित गिद्ध आवास स्थलों में पहुंचेंगे और यहां गिद्ध आवास देखेंगे और वृक्षों, चट्टानों पर बैठे गिद्ध को गणना में शामिल किया जाएगा। उड़ते हुए गिद्ध गणना में नहीं शामिल किए जाएंगे। प्रशिक्षित अमले के द्वारा बाइनाकुलर (दूरबीन) से गिद्धों की पहचान की जाएगी और मोबाइल एप में फोटो केप्चर कर अपलोड करते हुए गिद्धों की संख्या, आवास की संख्या, गिद्धों की प्रजाति और गिद्ध मेल, फीमेल, वयस्क, अवयस्क दर्ज किए जाएंगे तेंदूखेड़ा उप मंडल के चारों रेंज तेंदूखेड़ा तेजगढ़

झलौन तारादेही में आज सुबह 5 बजे से टीम गिद्ध गणना पर निकलेगी।

उप वनमंडल अधिकारी प्रतीक दुबे ने बताया कि तेंदूखेड़ा उप वनमंडल अधिकारी प्रतीक दुबे ने बताया कि आज से तीन दिवसीय गिद्ध गणना शुरू हो रही है जो कि दमोह जिले के साथ ही उप मंडल के चारों ओर होगी सुबह से स्टाफ गिद्ध गणना के लिए जंगलों में पहुंचेंगे और मोबाइल एप में फोटो केप्चर कर अपलोड करते हुए गिद्धो की संख्या एवं आवास का पता लगाएंगे उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पशुओं के इलाज में डाइक्लोफेनेक दवा का उपयोग न करें। साथ ही, मृत पशुओं के शवों में विषाक्त पदार्थ न मिलाएं, प्लास्टिक कचरे का सही निपटान करें और गिद्धों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा में सहयोग करें।

दर्दनाशक दवाओं के उपयोग से विलुप्त हो गए गिद्ध

गिद्धों की आबादी में गिरावट से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस गिरावट का प्रमुख कारण पशु चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेट्री दवा डाइक्लोफेनेक माना गया है। उपचारित पशुओं के मृत शरीर का सेवन करने पर गिद्धों में किडनी एवं आंत संबंधी गंभीर रोग उत्पहा हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। गिद्ध अत्यंत प्रभावी मुर्दाखोर पक्षी है, जो पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पशुओं के शवों का तीव्र एवं कुशलता से भक्षण कर उनसे फैलने वाली बीमारियों के प्रसार को रोकने में सहायक होते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र (ईको-सिस्टम) में गिद्धों का विशेष महत्व है।

खेत में मिला था महिला का शव, टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा

पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार चरित्र शंका में वारदात को दिया था अंजाम

धार। दोपहर मेट्रो

गंधवानी पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी को वारदात की सूचना मिलने के महज दो घंटे के भीतर दबोच लिया है। आरोपी ने चरित्र शंका के चलते अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था।

जानकारी के अनुसार 21 मई को सूचनाकर्ता राहुल पिता गुलाब ने पुलिस को सूचना दी कि उसके जीजा हीरालाल पिता मानसिंह, निवासी ग्राम बेहड़दा ने उसकी बहन किरण की हत्या कर दी है। किरण का शव हीरालाल के ही खेत में पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौका मुआयना किया और आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया। पुलिस अधीक्षकसचिन शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

विजय डावर द्वारा तत्काल आरोपी की पतारसी और गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। एसडीओपी मनावर ब्रजेश कुमार मालवीय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गंधवानी प्रदीप खन्ना व चौकी प्रभारी जीराबाद रविन्द्र चौधरी ने तत्काल क्षेत्र में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। पुलिस टीम की घेराबंदी घटना की सूचना मिलने के महज दो घंटे के भीतर ही आरोपी हीरालाल पिता मानसिंह चौहान निवासी ग्राम बेहड़दा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी हीरालाल की दो पत्नियां हैं। वह अपनी पत्नी किरण के चरित्र पर शंका करता था, इसी विवाद के चलते उसने किरण की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। इस अंधे कत्ल का महज दो घंटे में खुलासा करने में गंधवानी थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना, जीराबाद चौकी प्रभारी सउनि रविन्द्र चौधरी, प्रधान आरक्षक सुखराम, आरक्षक शैलेंद्र यादव, चेनसिंह, संतोष नागर और कैलाश का सराहनीय योगदान रहा।

तस्वीरों में नवगठित सेंचुरी: दुर्लभ सेई और शावकों को पीठ पर लादे दिखी मादा भालू

सागर। दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित नए डॉ. भीमराव आंबेडकर अभयारण्य (बंडा-शाहगढ़) से वन्यजीव प्रेमियों को उत्साहित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वन विभाग के कैमरा ट्रैप में एक दुर्लभ सेई और अपने दो शावकों को पीठ पर लादे घूमती एक मादा भालू की दुर्लभ झलक कैद हुई है। इन तस्वीरों में इस नवगठित सेंचुरी की जैविक विविधता बखूबी झलक रही है।

सेंचुरी क्षेत्र में लगाए गए कैमरा ट्रैप में वन्य जीवों की सक्रियता लगातार दर्ज की जा रही है। ताज़ा फुटेज में कांटों से ढका शर्मीला जीव सेई आमतौर पर मानवीय आहट से दूर रहता है, लेकिन विनायका-बरेठी के जंगलों में इसकी मौजूदगी दर्ज हुई है। वहीं एक भारी-भरकम मादा भालू अपने दो बच्चों को

सुरक्षित ढंग से पीठ पर बैठाकर जंगल का सफर तय करती नजर आ रही है। जबकि इसी वन मंडल में तेंदुए की भी चहल-पहल है, जहाँ एक वीडियो में तेंदुआ बंदर का शिकार करता दिखाई दे रहा है। सेई एक बड़े आकार का निशाचर शाकाहारी प्राणी है, जिसके शरीर पर नुकीले कांटों का कवच होता है। यह एक अत्यंत शर्मीला प्राणी है। खतरे का आभास होने पर यह अपने कांटों को खड़ा कर लेता है और पीछे की ओर हमला कर शिकारी को घायल कर देता है। कांटों को देखते हुए इस जीव का शिकार तेंदुए और बाघ भी नहीं कर पाते हैं। डॉ. बीआर आंबेडकर सेंच्युरी में सेई का दिखना स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है।

भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पन्ना टाइगर रिजर्व से लेकर यूपी के ललितपुर और नौरादेही-रातापानी के बीच बाघों के मूवमेंट के लिए एक नेचुरल कॉरिडोर (प्राकृतिक गलियारा) का काम करता है। वन्य प्राणी विशेषज्ञ एवं पारिस्थिति तंत्र के जानकारों के अनुसार की सक्रियता से यह क्षेत्र भविष्य में ईको-टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन सकता है। रेंजर सर्वेश सोनी अनुसार अभयारण्य क्षेत्र में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, अस्थायी चेक पोस्ट को प्रारम्भ किया जा रहा, साथ ही विभागीय गश्ती में भी कसावट लाई जा रही है, भविष्य में डॉ भीमराव अंबेडकर अभयारण्य का सागर जिले के मानचित्र पर पर्यटन में अलग ही स्थान होगा।

मेट्रो एंकर जापान के काकामिघारा में 26 मई से 6 जून तक होगा टूर्नामेंट

हॉकी सितारों ने रचा इतिहास: अंश, गाजी और महक का भारतीय टीम में चयन, जापान में दिखाएंगे दम

नर्मदापुरम/इटारसी।। दोपहर मेट्रो

शहर के खेल इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। इटारसी और नर्मदापुरम की माटी में पले-बढ़े तीन प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ियों ने एक साथ भारतीय टीम में जगह बनाकर जिले को गौरवान्वित किया है। आगामी अंडर-18 एशिया कप के लिए पुरुष टीम में अंश बहुतरा व गाज़ी खान और महिला टीम में गोलकीपर महक परिहार का चयन हुआ है।

भारतीय खेल प्राधिकरण के टॉप्स डिवीजन द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जापान के काकामिघारा में 26 मई से 6 जून तक आयोजित किया जाएगा। पुरुष टीम की कमान पूर्व कप्तान सरदार सिंह के हाथों में है, वहीं महिला टीम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी। चयनित खिलाड़ियों में अंश बहुतरा अपनी बेहतरीन रक्षात्मक तकनीक (डिफेंडर) के लिए जाने जाते हैं,

जबकि गाज़ी खान अपनी आक्रामक शैली और तेज रफ्तार के कारण फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में गोल दागने की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, महक परिहार भारतीय महिला टीम की गोलपोस्ट की रक्षा (गोलकीपर) करते हुए दीवार बनकर खड़ी होंगी। ये तीनों ही खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय दौरे पर सरकारी खर्च पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हॉकी नर्मदापुरम (इटारसी) के अध्यक्ष राजेंद्र तोमर, सचिव साजिद मलिक, कोषाध्यक्ष सर्वजीत सिंह सैनी और कोच कन्हैया गुरयानी, पवन सिंह, जयसिंह भदौरिया सहित स्थानीय खेल प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त किया है। हॉकी नर्मदापुरम ने इन खिलाड़ियों की प्रतिभा पर भरोसा जताने के लिए हॉकी मध्य प्रदेश के कोच समीर दाद, हॉकी अकादमी ग्वालियर की वंदना उईके और हॉकी मध्य प्रदेश के महासचिव लोक बहादुर का आभार व्यक्त किया है। अब पूरा शहर और जिला अपने इन तीनों होनहारों के जापान में शानदार प्रदर्शन और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लौटने की मंगलकामना कर रहा है।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल खण्ड, भोपाल
अरविन्द विहार, लहारपुर डेम के समीप, बाग मुगालिया, भोपाल दूरभाष नं. 2930001

क्रमांक 698/का.यं./ लोक स्वा./मेके. खण्ड/ भोपाल/2026/ दिनांक. 20/05/2026

मासिक किराये पर निरीक्षण वाहन उपलब्ध कराने हेतू निविदा क्रमांक 07/2026-27 ऑन-लाईन निविदा क्रमांक 2026_PHED_508577_1 दिनांक 20.05.2026

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मैकेनिकल खण्ड भोपाल के अंतर्गत् वर्ष 2026-27 के दौरान आवश्यकता पड़ने पर, मासिक किराये पर, निरीक्षण वाहन उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी मध्य प्रदेश में पंजीकृत प्रतिष्ठित एजेन्सियों से, जिन्हें इस तरह के कार्यों का अनुभव हो तथा प्रदायकर्ता/फर्म के नाम पर कम से कम 10 (निविदा में दर्शित / समकक्ष) वाहन स्वयं अथवा ऐजेन्सी के नाम होना अनिवार्य है, से मासिक किराये की प्रस्तावित दरों पर ऑन लाईन डिजिटली हस्ताक्षरित निविदा दिनांक 05.06.2026 सायं 17.30 बजे तक एपेंडिक्स 2.10 पर आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु अभिलेखों जैसे धरोहर राशि, फार्म फीस एवं अन्य वांछित दस्तावेज दिनांक 05.06.2026 सायं 17.30 बजे तक https://mptenders.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य है। निविदा फार्म दिनांक 05.06.2026 तक बेबसाईट https://mptenders.gov.in पर राशि रूपये 5000/-(रु. पाँच हज़ार) मात्र भुगतान कर ऑनलाईन क्रय किये जा सकते हैं।

निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

निविदा प्राक्कलन की अनुमानित लागत राशि (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	निविदा का मूल्य (रू.)	निविदा आनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि	निविदा की समयावधि
49,98,400.00	50,000.00	5,000.00	05.06.2026 17.30 बजे तक	08.06.2026 15.00 बजे	कार्यादेश दिनांक से 08 माह

निविदा से संबंधित अन्य समस्त शर्तें एवं विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर ऑन-लाईन निविदा क्रमांक 2026_PHED_508577_1 दिनांक 20.05.2026 उपलब्ध है।

जी-13203/26

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वा.यॉं.वि.मेकेनिकल खण्ड भोपाल

कार्तिक बोले- बोझ न डालें

वैभव सूर्यवंशी को अगला सचिन तेंदुलकर न कहें

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा है कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर आईपीएल 2026 में धूम मचा रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की तुलना महान सचिन तेंदुलकर से कर उन पर बोझ न डाला जाए। कार्तिक ने कहा कि इस युवा खिलाड़ी के सामने आने वाली चुनौतियां बिल्कुल अलग होंगी। कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं। दिनेश कार्तिक ने एक पॉडकास्ट में कहा, वैभव जो कर रहा है, वह बहुत खास है। लेकिन मैं लोगों से यह नहीं चाहता कि वे उसे अगला सचिन% कहना शुरू कर दें। वह अभी सिर्फ 15 साल का है और इस उम्र में ऐसा शानदार प्रदर्शन कर रहा है। मेरा मानना है कि सचिन ने जो किया था, वह असाधारण था। वैभव के सामने आने वाली चुनौतियां बिल्कुल अलग होंगी। सचिन के सामने जितनी चुनौतियां मैदान पर थीं, उतनी ही मैदान के बाहर भी थीं। वैभव के सामने आने वाली चुनौतियां निश्चित रूप से मैदान के बाहर ज्यादा होंगी। उसके पास क्रिकेट के हुनर की कोई कमी नहीं है। उसे तो खेल के बाहर की चीजों से निपटना सीखना होगा।

2008 से लेकर 2026 तक आईपीएल में हुए बदलावों पर चर्चा करते हुए कार्तिक ने कहा, आईपीएल अपनी शुरुआत से लेकर आज जिस मुकाम पर है, वह पूरी तरह से एक अलग ही रूप ले चुका है। इस खेल ने तेजी से विकास किया है। इसमें बहुत कुछ बदल गया है। यह अब तक का सबसे तेजी से बढ़ने वाला फॉर्मेट है। यह बहुत से लोगों के लिए एक बेहतर जीवनशैली का जरिया बन गया है। साथ ही, यह उन सभी युवा लड़कों और लड़कियों के लिए एक बहुत ही मजबूत करियर विकल्प के तौर पर उभरा है, जो इस खेल को अपनाना चाहते हैं। बहुत ही कम समय में यह दुनिया के दूसरे खेल टूर्नामेंट्स को कड़ी टक्कर दे रहा है।

वैभव का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपने प्रदर्शन से दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को हैरान और रोमांचित किया है। सूर्यवंशी ने 13 मैचों में 579 रन बनाए हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सीजन में एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। इतना ही नहीं, वैभव आईपीएल के एक सीजन में 50+ छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं।

दिग्गज ज्वाला गुट्टा ने खोली भारतीय बैडमिंटन की पोल

सब समझौता कर रहे हैं, पर कोई बोलने को तैयार नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय बैडमिंटन की पूर्व स्टार खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने एक बार फिर भारतीय खेल व्यवस्था पर खुलकर हमला बोला है। अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली ज्वाला ने कहा कि भारतीय बैडमिंटन में चुप्पी और समझौते की संस्कृति बढ़ती जा रही है, जो खेल के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। एक इंटरव्यू में ज्वाला ने खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों और बैडमिंटन संघों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिस्टम की कमियों के बावजूद कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हर कोई एडजस्ट कर रहा है, समझौता कर रहा है। यहां तक कि एसोसिएशन भी। सबसे खराब बात यह है कि जो पूर्व खिलाड़ी अब संघ में जा रहे हैं, उन्हें भी यह बुरा नहीं लगता कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है।

चीन का उदाहरण देकर भारत की कमी गिनाई- ज्वाला गुट्टा ने भारतीय बैडमिंटन की तुलना चीन से करते हुए कहा कि वहां किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर तुरंत दूसरा विश्वस्तरीय खिलाड़ी तैयार मिल जाता है, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा, चीन को देखिए। अगर उनका एक वर्ल्ड चैंपियन चोटिल हो जाए तो दूसरा खिलाड़ी तैयार रहता है। वह एक-दो टूर्नामेंट खेलकर खुद वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। इसे बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं और हमारे पास यही नहीं है।उनके मुताबिक भारत में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर और सही समर्थन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से नई प्रतिभाएं लगातार सामने नहीं आ पा रही हैं।

प्रभाव नहीं है, इसलिए CSR फंड नहीं मिलता

ज्वाला ने अपनी अकादमी चलाने के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में गैर-लाभकारी अकादमी शुरू करने के बावजूद उन्हें आर्थिक मदद जुटाने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मैंने भी एक अकादमी खोली है और मुझे पता है कि डोनेशन हासिल करने में कितनी परेशानी होती है। यह पूरी तरह गैर-लाभकारी संस्था है, लेकिन मुझे छ्स्रफंड नहीं मिल रहा क्योंकि मैं उतनी प्रभावशाली नहीं हूं और मेरे रिश्ते दूसरों जैसे नहीं हैं। ज्वाला ने इशारों में यह भी कहा कि खेलों में कई बार प्रतिभा से ज्यादा पहचान और संपर्क मायने रखते हैं। पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता ज्वाला गुट्टा ने कहा कि उनका बेबाक रवैया ही उनके खिलाफ चला गया। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं खुलकर अपनी बात कहती हूं, इसलिए सिस्टम मुझे पसंद नहीं करता। जो लोग अभी खेलों को चला रहे हैं, चाहे बैडमिंटन हो या कोई और क्षेत्र, वे मुझे पसंद नहीं करते। ज्वाला ने अपने करियर के दौरान बैडमिंटन अधिकारियों के साथ हुए विवादों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई कभी निजी फायदे के लिए नहीं थी, बल्कि खेलने के अधिकार के लिए थी। उन्होंने कहा, मैंने कभी अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं मांगा। मैं हाई कोर्ट सिर्फ खेलने के अधिकार के लिए गई थी क्योंकि कोई मुझे खेलने से रोकना चाहता था।

जूनियर खिलाड़ियों को मदद मिली, मैं खुद खर्च उठाती रही

ज्वाला ने दावा किया कि राष्ट्रीय चैंपियन और विश्व नंबर-5 होने के बावजूद उन्हें कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट अपने खर्च पर खेलने पड़े। उन्होंने कहा, मैं 2007, 2008 और 2009 में राष्ट्रीय चैंपियन थी, लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट अपने पैसों से खेलती थी। मेरे जूनियर खिलाड़ियों को भारतीय टीम के साथ भेजा जाता था और वे क्वालीफाइंग राउंड में हार जाते थे, जबकि मैं टूर्नामेंट जीतती थी। उनके अनुसार यह अनुभव बेहद निराशाजनक था और इससे उन्हें सिस्टम की वास्तविकता समझ आई। ज्वाला गुट्टा ने कहा कि जब खिलाड़ी मुश्किल में होते हैं तो वे चाहते हैं कि कोई उनके लिए आवाज उठाए, लेकिन जब वह खुद संघर्ष कर रही थीं तब किसी खिलाड़ी ने उनका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा, जब खिलाड़ी परेशानी में होते हैं तो चाहते हैं कि कोई उनके लिए बोले। लेकिन जब मैं मुश्किल में थी, तब एक भी खिलाड़ी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई।

सात्विक के बयान का भी किया समर्थन

ज्वाला की यह प्रतिक्रिया हाल ही में भारतीय डबल्स स्टार सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी के बयान के बाद आई है। सात्विक ने हाल में कहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों को वह पहचान नहीं मिलती जिसकी वे हकदार हैं। इस पर ज्वाला ने कहा, अब देखिए, सात्विक ने क्या कहा? उसने कहा कि कोई हमारी तरफ देखता ही नहीं। लेकिन लोग क्यों देखेंगे? आप लोग कुछ बोलते ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी सफलता और पहचान हासिल कर चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे अगली पीढ़ी और देश के बैडमिंटन के लिए आवाज उठाएं।

सिर्फ खेल तक सीमित मत रहिए

ज्वाला का मानना है कि कई खिलाड़ी खेल से बाहर अपनी अलग पहचान नहीं बना पाते क्योंकि वे सार्वजनिक तौर पर अपनी राय रखने से बचते हैं। उन्होंने कहा, जब आप बैडमिंटन छोड़ देंगे तो लोग आपके बारे में बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपने कभी कुछ कहा ही नहीं। आपने बैडमिंटन के अलावा किसी मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखी। अपने संघर्ष और बेबाकी के पीछे ज्वाला ने अपने परिवार को सबसे बड़ा सहारा बताया। उन्होंने कहा, मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे परिवार ने मेरा समर्थन किया, इसलिए मैं संघ के खिलाफ लड़ पाई। अंत में उन्होंने समाज में जिम्मेदारी और विशेषाधिकार को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, अगर विशेषाधिकार प्राप्त लोग उन लोगों के लिए नहीं बोलेंगे जो उतने विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं, तो हमारे देश का क्या होगा?

आईपीएल 2026 ने बढ़ाई सूर्यकुमार यादव की टेंशन...

टीम इंडिया की छिन सकती है कप्तानी

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में अगर किसी बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट की परिभाषा बदली है, तो वह नाम सूर्यकुमार यादव है मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता, गेंदबाजों पर लगातार दबाव और 360 डिग्री बल्लेबाजीज इन सबने सूर्यकुमार यादव को दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में शामिल कर दिया। लेकिन क्रिकेट का यही खेल कभी-कभी सबसे बड़े सितारों को भी मुश्किल दौर दिखाता है। आईपीएल 2026 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां उम्मीदों का पहाड़ लेकर उतरे सूर्यकुमार यादव बल्ले से वैसा असर छोड़ने में नाकाम रहे, जिसकी उनसे आदत पड़ चुकी थी। एक तरफ भारतीय टी20 टीम की कप्तानी में सूर्यकुमार का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उनकी कप्तानी में भारत ने 2025 टी20 एशिया कप जीता और फिर 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की। बड़े टूर्नामेंट में टीम को संभालने और दबाव झेलने की उनकी

क्षमता की हर तरफ तारीफ हुई। लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल 2026 में उनका बल्ला लगभग शांत ही रहा। मुंबई इंडियंस को इस सीजन अपने सबसे अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाज से बड़ी पारियों की उम्मीद थी, लेकिन कई मौकों पर टीम को निराशा हाथ लगी। यादव ने इस सीजन 12 पारियों में सिर्फ 210 रन बनाए। एवरेज 17।50 का रहा और पूरे सीजन में उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक निकला। यह वही बल्लेबाज है, जिसने पिछले सीजन IPL 2025 में 700 से ज्यादा रन ठोक दिए थे और गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था।

मुंबई इंडियंस के अभियान पर पड़ा असर

मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी लंबे समय तक सूर्यकुमार यादव के इर्द-गिर्द घूमती रही है। जब वह लय में होते हैं तो टीम का मिडिल ऑर्डर लगभग अजेय नजर आता है। लेकिन इस सीजन उनकी खराब फॉर्म का असर पूरी टीम पर दिखाई दिया। कई मैचों में मुंबई अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। कई मौकों पर टीम दबाव में बिखर गई क्योंकि वह %सूर्यकुमार स्पेशल% पारी देखने को नहीं मिली, जिसकी आदत मुंबई इंडियंस को वर्षों से रही है। सबसे बड़ी बात यह रही कि सूर्यकुमार यादव इस सीजन मैच फिनिश करने वाली पारियां भी नहीं खेल सके। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास और फ्लो कम नजर आया, जो आमतौर पर उनकी पहचान माना जाता है।

गिल-सुदर्शन का तूफान, सिराज-रबाडा की तबाही,

गुजरात टाइटन्स ने ऐसे तोड़ा CSK का प्लेऑफ का सपना

अहमदाबाद। गुजरात टाइटन्स ने आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराकर प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया. अहमदाबाद में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात ने हर विभाग में चेन्नई को पीछे छोड़ते हुए टॉप-2 में जगह मजबूत कर ली.

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटन्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 229 रन बनाए. कप्तान शुभमन ग?िल और साई सुदर्शन ने एक बार फिर टीम को धमाकेदार शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 74 गेंदों पर 125 रन जोड़कर ढ्ढक्क इतिहास में अपनी सातवीं शतकीय साझेदारी पूरी की. गिल शुरुआत से ही आक्रामक नजर आए. उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतक ठोका और 37 गेंदों पर 64 रन बनाए. उनकी पारी में शानदार

कट, स्ट्रेट ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स देखने को मिले. खासकर स्पेंसर जॉनसन के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की. दूसरी ओर साई सुदर्शन ने एक बार फिर संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया. उन्होंने 53 गेंदों पर 84 रन बनाए और लगातार पांचवीं फिफ्टी जड़ी. नूर अहमद और अंशुल कंबोज के खिलाफ उनके बड़े शॉट्स ने गुजरात को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. इसके बाद जोस बटलर ने अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 27 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाए।

मनोरंजन | **बॉलीवुड का कोना**

32 साल पहले रचा गया था इतिहास

जब सुष्मिता ने दुनिया को बताया था भारत का दम सोशल मीडिया पर छलका गर्व -भावनाओं का रंग

भारतीय सौंदर्य और आत्मविश्वास की मिसाल मानी जाने वाली सुष्मिता सेन ने एक बार फिर अपने प्रशंसकों को भावुक कर दिया। उनके मिस यूनिवर्स बनने के ऐतिहासिक पल को पूरे 32 साल हो गए। इस खास अवसर पर अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपने चाहने वालों और फिलीपींस के लोगों का दिल से आभार व्यक्त किया।

सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें वह बस में बैठकर विमान की ओर जाती दिखाई दे रही हैं। तस्वीर में उनकी वही आत्मविश्वास से भरी मुस्कान नजर आई, जिसने 1994 में पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अभिनेत्री ने लिखा कि पिछले 32 वर्षों से उनके चेहरे पर बनी यह मुस्कान लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से कायम है। उन्होंने फिलीपींस के लोगों के प्रति भी अपना विशेष प्रेम जताया और कहा कि वहां मिला स्नेह हमेशा उनके दिल में बसा रहेगा।

साल 1994 भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं के

इतिहास में बेहद खास माना जाता है। उसी वर्ष सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। ऐश्वर्या को उस समय बेहद मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सुष्मिता ने अपनी बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के दम पर मिस इंडिया का ताज अपने नाम कर लिया।

77 देशों को पीछे छोड़ बनीं थीं विश्व सुंदरी

फिलीपींस में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सुष्मिता सेन ने 77 देशों की प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए भारत के लिए पहला मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। यह उपलब्धि केवल सौंदर्य की नहीं, बल्कि भारतीय महिलाओं के आत्मविश्वास और क्षमता की भी जीत मानी गई।

विश्व सुंदरी बनने के बाद सुष्मिता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने दस्तक से अभिनय करियर की शुरुआत की। हालांकि उन्हें असली पहचान बीवी नंबर 1 से मिली। इसके बाद उन्होंने आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया जैसी सफल फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा।

पैप्स ने फिर किया शर्मिंदा, सलमान के बाद सारा तेंदुलकर पर किया गंदा कमेंट

फैन्स अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की झलक पाने को बेताब रहते हैं। इसलिए पैपराजी सेलिब्रिटीज को देखते ही हर एंगल से उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कई दफा सोशल मीडिया सेलेब्स के ऊट-पटांग वीडियोज-फोटोज वायरल होते हैं। इस दफा सारा तेंदुलकर ने अपनी वायरल फोटो पर रिएक्ट किया है। भद्दे कैप्शन के साथ उनका वीडियो वायरल करने के लिए उन्होंने पैप्स को लताड़ लगाई है।

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए पैप्स पर गुस्सा निकाला है। सारा ने जो पोस्ट शेयर की है, उसमें वो ब्लू जींस में एयरपोर्ट पर एंट्री लेते दिख रही हैं। तस्वीर में सारा का बैक दिखाई दिया। तस्वीर का कैप्शन था मोटी वाली सारा है, बगल वाली भाभी है। जब ये पोस्ट सारा की नजरों के सामने आई, तो उनका पारा हाई हो गया।

सारा ने पोस्ट शेयर करते हुए पैप्स को टैग किया और लिखा कि ये बहुत घटिया हरकत है। हमें अकेला छोड़ दो। उन्होंने ये भी लिखा कि पोस्ट डिलीट करने से आप कम घटिया नहीं हो जाओगे। सारा को उनके फैन्स का सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि इतने भद्दे कैप्शन पर ऐसी नाराजगी जाहिर है। सारा से पहले सलमान खान भी पैपराजी पर भड़क चुके हैं। दो दिन पहले सलमान खान मुंबई के एक हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट हुए। उन्हें देखकर पैपराजी की भीड़ जमा हो गई। सलमान ने पैपराजी पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि अगर अस्पताल में तुम्हारा कोई अपना होता, तो क्या तब भी ऐसी हरकत करते। कई बार हमें सेलेब्स का गुस्सा दिखता है, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं आखिर उन्हें गुस्सा आया क्यों। गुस्से के लिए सेलेब्स को ट्रोल करना आसान है। पर उसकी तह तक पहुंचना आसान है। हर बार सेलेब्स का गुस्सा फिजूल नहीं होता है। आज तक कभी सारा को इस तरह नाराज होते नहीं देखा गया। हद पार करने पर उनका ऐसा रिएक्शन बिल्कुल जायज है।

मेट्रो बाजार

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पहली तिमाही में भारत में सबसे अधिक रही प्रॉपर्टी यील्ड

नई दिल्ली। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत ने कैलेंडर ईयर 2026 की पहली तिमाही में सबसे अधिक रियल एस्टेट यील्ड दी है और इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम में सालाना आधार पर 189 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। सीबीआरई की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कैप रेट कार्यालय, खुदरा, लॉजिस्टिक्स, होटल और छात्र आवास क्षेत्रों में इस क्षेत्र के अन्य सभी बाजारों की तुलना में लगातार आगे निकल रहे हैं, कुछ मामलों में तो यह अंतर 320 आधार अंकों तक का है। भारत में 2026 की पहली तिमाही में रियल एस्टेट में निवेश वॉल्यूम एक वर्ष पहले के 839.85 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2,295.19 मिलियन डॉलर हो गई, जो कि सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर ने निवेश वॉल्यूम में 364 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल किया। सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ (भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा, ÷भारत की आर्थिक बुनियाद, बढ़ते कॉरपोरेट आधार और युवा, उपभोग-उन्मुख आबादी के कारण हम सभी क्षेत्रों में वास्तविक और व्यापक मांग देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अब तक सतर्क रहे वैश्विक निवेशक अब यहां पूंजी लगाने के लिए सक्रिय रूप से इच्छुक हैं, और हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे अधिक संस्थागत स्तर के उत्पाद बाजार में आएंगे, यह गति और मजबूत होगी। रिपोर्ट में घरेलू संस्थानों, फैमिली ऑफिसों और वैश्विक पूंजी बाजार के खिलाड़ियों की निरंतर रुचि का जिक्र किया गया है।

आरबीआई सरकार को ट्रांसफर करेगी रिकॉर्ड 3.5 लाख करोड़ रुपए तक का डिविडेंड : रिपोर्ट

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वित्त वर्ष 26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड सरप्लस डिविडेंड का भुगतान करेगी और यह राशि 2.7 लाख करोड़ रुपए से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि डिविडेंड को सरकार को ट्रांसफर करने के लिए आरबीआई के बोर्ड की बैठक शुक्रवार को प्रस्तावित है। अगर आरबीआई बोर्ड संभावित राशि के ऊपरी बैंड को डिविडेंड के रूप में मंजूरी देता है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को ट्रांसफर की गई अब तक की यह सबसे बड़ी राशि होगी। बीते वर्ष आरबीआई ने केंद्र को 2.69 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर किया था।

अनुमानित डिविडेंड में यह तेज वृद्धि ऐसे वर्ष के बाद हुई है जिसमें आरबीआई को मुद्रा अस्थिरता, विदेशी मुद्रा संचालन और निवेश से हाई यील्ड का लाभ मिला। संभावित डिविडेंड भुगतान में एक प्रमुख योगदान वित्त वर्ष 2026 के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के लगभग 10 प्रतिशत अवमूल्यन का रहा, जिससे कथित तौर पर आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में वृद्धि हुई और उसकी बैलेंस शीट का विस्तार हुआ।

केंद्रीय बैंक ने रुपए की अत्यधिक कमजोरी को रोकने के लिए डॉलर बेचकर मुद्रा बाजारों में सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से भी लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 688 अरब डॉलर हो गया, जिससे आरबीआई की आय में और मजबूती आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा संचालन के अलावा, निवेश और मुद्रा मुद्रण गतिविधियों से प्राप्त आय ने भी अनुमानित सरप्लस में योगदान दिया।

100 किमी दूर दुश्मन को तबाह करने वाले 'वायु अस्त्र' का सफल परीक्षण

भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत

नई दिल्ली। भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती देने की दिशा में पुणे की रक्षा कंपनी निबे लिमिटेड ने बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है। कंपनी ने कहा कि उसने अपनी 100 किलोमीटर रेंज वाली 'वायु अस्त्र' लोइटरिंग म्यूनिशन प्रणाली का नो-कॉस्ट, नो-कमिटमेंट प्रदर्शन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ (मलारी) में आयोजित किए गए।

कंपनी के बयान के अनुसार, पोखरण में 18 और 19 अप्रैल को जबकि जोशीमठ (मलारी) में 26 और 27 अप्रैल को परीक्षण किए गए। 'वायु अस्त्र-1' लोइटरिंग म्यूनिशन के एंटी-पर्सनल वैरिएंट ने राजस्थान के पोखरण रेंज में अपना पहला एनसीएनसी प्रदर्शन सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान प्रणाली ने 10 किलोग्राम वारहेड के साथ लक्ष्य को साधा। रक्षा मंत्रालय की पूंजीगत खरीद प्रक्रिया में उत्पाद परीक्षण नो-कॉस्ट, नो-कमिटमेंट आधार पर किए जाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार परीक्षण के लिए कोई भुगतान नहीं करती और न ही बाद में उत्पाद खरीदने की बाध्यता होती है।

कंपनी ने दावा किया कि वायु अस्त्र ने 100 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को पहली ही कोशिश में निशाना बनाया। इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल एक मीटर से कम रहा। साथ ही प्रणाली ने अबॉर्ट-अटैक और री-अटैक क्षमता का भी सफल प्रदर्शन किया। कंपनी के अनुसार, यह लोइटरिंग म्यूनिशन जरायली तकनीक पर आधारित है।

न्यूज विंडो

ईडी का बड़ा एक्शन, कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक कई जगहों पर छापेमारी

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय ने सुबह से कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई जमीन कब्जाने और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में की जा रही है, जिनमें कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर सिन्हा बिस्वास और कुख्यात स्थानीय भूमि माफिया बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू का नाम सामने आया है।सिन्हा बिस्वास और सोना पप्पू को इसी महीने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों एजेंसी की हिरासत में हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान मिले इनपुट और पूछताछ में सामने आए नामों के आधार पर शुक्रवार को कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई।सूत्रों के मुताबिक, ईडी की एक टीम शुक्रवार सुबह दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर इलाके के चक्रबेड़िया स्थित एक कारोबारी के घर पहुंची। अधिकारियों ने वहां पहुंचते ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया और दस्तावेजों व वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की।इसके कुछ ही देर बाद ईडी की दूसरी टीम सेंट्रल कोलकाता के रॉयड स्ट्रीट स्थित एक होटल पहुंची। जांच अधिकारियों ने सबसे पहले होटल मैनेजर से पूछताछ की और उसके बाद होटल परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया। सूत्रों के अनुसार, होटल मालिक को भी तुरंत होटल पहुंचने के लिए कहा गया है ताकि उससे पूछताछ की जा सके।

चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी अमेरिका में किया गया नया बिल पेश

वाशिंगटन। अमेरिका में चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दो वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसदों ने चीन के सैन्य-औद्योगिक नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर तेजी से प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से नया विधेयक पेश किया है। सांसदों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाने वाली चीनी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई में अब और देरी नहीं की जा सकती।रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट और प्रतिनिधि एलिस स्टेफानिक ने 'सीसीपी सैंक्शंस शॉट क्लॉक एक्ट' नाम का विधेयक पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को उन चीनी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ एक साल के भीतर कार्रवाई करनी होगी, जिन्हें अमेरिकी सरकार सुरक्षा के लिए खतरा मानती है।विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करना है।

एक गोली से दो मौतें: पत्नी को पीठ से लगा व्यापारी ने खुद को गोली से उड़ाया

रामपुर। आर्थिक तंगी और पत्नी की बीमारी से परेशान कस्बे के मुख्य बाजार निवासी बर्तन व्यापारी सुनील रस्तोगी (50) ने सुबह पत्नी नेहा रस्तोगी (45) को पीठ से लगाकर खुद को लाइसेंसी राइफल से उड़ा लिया। एक ही गोली से दोनों की मौत हो गई। कमरे में मिली डायरी से आत्महत्या की पुष्टि हुई है। कस्बे के मुख्य बाजार निवासी सुनील रस्तोगी के परिवार में पत्नी नेहा रस्तोगी, बेटा पीयूष रस्तोगी व बेटी कृषि रस्तोगी हैं। वह बर्तन का कारोबार कर परिवार का पालन पोषण करते थे। पत्नी को कैंसर होने पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इससे वह अवसाद में थे। सुबह करीब 7:30 बजे व्यापारी के घर की पहली मंजिल से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर भूतल पर मौजूद बेटा पीयूष, बेटी कृषि पहुंचे, जहां पर सुनील रस्तोगी और उनकी पत्नी के रक्तरंजित शव पड़े मिले। सुनील रस्तोगी के हाथ के पास स्टील का डंडा और नजदीक ही 315 बोर की राइफल पड़ी थी। सूचना पर सीओ देवकीनंदन और कोतवाल प्रदीप कुमार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए।

ईज ऑफ लिविंग से विकसित भारत तक

पीएम मोदी बोले-विकास की गति तेज करने के लिए सुधार जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर अहम जानकारी साझा की। विदेश दौरों से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 'सेवा तीर्थ' में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल हुए। यह वर्ष 2026 की पहली पूर्ण मंत्रिपरिषद बैठक थी। इससे पहले ऐसी बैठक 4 जून 2025 को आयोजित की गई थी।

बैठक में इन विषयों पर की गई चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि बैठक में 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में सुधारों को और आगे बढ़ाने व विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर तौर-तरीकों और नए विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

बेहतर माहौल तैयार करने पर जोर

प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि मंत्रिपरिषद की बैठक बेहद सार्थक रही और इसमें शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, आम लोगों के जीवन को आसान करने व कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर

विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसे सुधारों को गति देना है, जो देश को तेज विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई, जब अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। भारत सरकार लगातार ईंधन आपूर्ति, महंगाई और ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

संसाधनों के समझदारी से उपयोग की अपील

इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देशवासियों से संसाधनों के समझदारी से उपयोग की अपील भी की थी। उन्होंने लोगों से जहां संभव हो 'वर्क फ्रॉम होम' अपनाने, अधिक से अधिक ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता देने और ईंधन की बचत करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने कम से कम एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचने और अनावश्यक विदेश यात्राओं से परहेज करने की भी सलाह दी थी।

तमिलनाडु कैबिनेट का फिर से हुआ विस्तार, IUML-VCK के नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

चेन्नई। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का आज फिर से विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में दो नए चेहरों को जगह दी है। इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता एएम शाहजहां और वीसीके के नेता वन्नी अरासु शामिल हैं।

दोनों नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

आज सुबह इन दोनों नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। एएम शाहजहां पापनाशम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वे अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं, वन्नी अरासु टिंडीवनम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे वीसीके पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इन दोनों नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह आज शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे चेन्नई के लोक भवन में संपन्न हुआ।

पहले 23 ने ली थी शपथ

यह विस्तार सरकार की मजबूती और सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री विजय ने अपनी कैबिनेट का बड़ा विस्तार किया था। उस समय 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। उस विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस पार्टी की सरकार में वापसी को लेकर हुई थी। करीब 59 साल के लंबे समय के बाद कांग्रेस तमिलनाडु में किसी क्षेत्रीय दल की सरकार का हिस्सा बनी है। पिछली कैबिनेट सूची में राज्य के लगभग हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया था। इसमें थूथुकुडी से श्रीनाथ, अविनाशी से कमाली एस और कांचीपुरम से आरवी रंजीतकुमार जैसे नेताओं को जगह मिली थी। साथ ही कुंभकोणम, कडलूर और कोयंबटूर जैसे शहरों के प्रतिनिधियों को भी मंत्री बनाया गया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का फैसला

वर्किंग वाइफ से घर के खर्च में योगदान मांगना क्रूरता नहीं

मुंबई, एजेंसी

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी कामकाजी पत्नी से अपने वेतन को घर के खर्चों में लगाने के लिए कहना अपने आप में गैरकानूनी मांग या क्रूरता नहीं माना जा सकता।

जस्टिस वृषाली जोशी ने नागपुर के एक व्यक्ति और उसके माता-पिता के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया। यह मामला मानकापुर पुलिस स्टेशन में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के लिए आईपीसी की धारा 498ए और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान के लिए धारा 504 के तहत दर्ज किया गया था।अदालत ने

इस बात पर गौर किया कि शिकायतकर्ता पत्नी, जो एक सरकारी कर्मचारी है, का आरोप था कि उस पर अपना वेतन सौंपने का दबाव डाला गया क्योंकि वह कथित तौर पर घर का काम नहीं करती थी।हालांकि, आरोपों और मामले से जुड़े सबूतों की जांच के बाद जस्टिस जोशी ने स्पष्ट किया कि इस तरह के दावों से वैवाहिक कानून के तहत क्रूरता के आवश्यक तत्व साबित नहीं होते हैं।

नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी का हमला, बोले- छात्रों की आवाज दबाने के लिए भाजपा सरकार चला रही लाठी

नई दिल्ली, एजेंसी

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक के चलते मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट रद्द किए जाने के बाद राज्यों में चल रहे कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की राज्य सरकारें युवा कांग्रेस तथा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा रही हैं।

मगर कांग्रेस डरने वाली नहीं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तथा देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बन जाता।कांग्रेस नेता ने कहा कि यह लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया है।

राजस्थान कांग्रेस के नेतृत्व में जयपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए बड़े विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई का प्रदेश

कांग्रेस हैंडल से साझा किए गए वीडियो को एक्स पर रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे। क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया।'

मोदी जी ने न जिम्मेदारी ली न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया

उन्होंने कहा, 'कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी और मोदी जी ने न जिम्मेदारी ली, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, न एक शब्द कहा। अब जब छात्र,एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं तो भाजपा की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं हैं।'

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी पेपर लीक पर सरकार को घेरते हुए एक्स पोस्ट में कहा कि जो लोग नीट परीक्षा को साफ-सुथरा नहीं रख सकते उनसे क्या उम्मीद की जाए।

मेट्रो एंकर

रिपोर्ट में दावा-युद्धविराम पर बातचीत के बीच खौफ में नेतन्याहू

खाड़ी देशों पर ईरान कर सकता है अचानक हमला

तेल अवीव, एजेंसी

इस्रायल को अंदेशा है कि ईरान उस पर और खाड़ी देशों पर अचानक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर सकता है। यह डर ऐसे समय में जताया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। 'जेरूसलम पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, खुफिया अधिकारियों ने इस संभावित खतरे की जानकारी दी है।

इस खतरे को देखते हुए इस्रायल के रक्षा मंत्री इस्रायल काट्ज और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ईरान कूटनीतिक कोशिशों के पूरी तरह नाकाम होने से पहले ही हमला करने की कोशिश कर सकता है। अधिकारियों ने इस संभावित हमले की तुलना 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' और 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' के शुरुआती चरणों से की है।

ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेदों की भी खबरें

वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कुछ मतभेदों की खबरें भी आई हैं। इसके बावजूद, दोनों देशों की सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस्रायली वायुसेना और आईडीएफ के अधिकारी अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे ईरान की संदिग्ध सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ईयाल जमीर लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि हमले की स्थिति में मिलकर जवाब दिया जा सके।पिछले एक महीने में अमेरिका से इस्रायल आने वाले सैन्य सामान की सप्लाई में काफी तेजी आई है।

दोनों देशों ने मिलकर मिसाइलों को रोकने वाले सिस्टम, तकनीक और सॉफ्टवेयर को और भी बेहतर बनाया है। 'वल्ला' की एक रिपोर्ट के अनुसार, खतरों की पहचान करने और उन्हें हवा में ही नष्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई है।

परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे

राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने साफ किया कि वे ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में लेकर उसे नष्ट कर देंगे। माना जाता है कि ईरान के पास करीब 900 पाउंड अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है, जो हथियार बनाने के लिए काफी है। इस्रायल शुरू से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। इस्रायल का मानना है कि सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों की वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक राजेश सिरोठिया द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। संपादक राजेश सिरोठिया स्थानीय संपादक अनिल शर्मा* आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) फोन : 0755-7963564